● वर्ष-4
● अंक-97
रायपुर, रविवार
01 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» महिला केंद्रित कहानियों...

चिन्मय दास के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार

कोलकाता। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को एक और हिंदू पुजारी श्याम दास प्रभु को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक श्याम दास प्रभु, चिन्मय दास से मिलने पहुंचे थे। श्याम दास को बिना किसी आधिकारिक वारंट के गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता राधारमण दास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक और ब्रह्मचारी श्याम दास प्रभु को आज चटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, कुंडलिधाम मठ के प्रवक्ता कुशल बरुण चक्रवर्ती ने भी दावा किया कि हिंदू नेता और कुंडलिधाम मठ के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास के दो सहयोगियों आदिनाथ प्रभु और रंगनाथ दास को चटगांव शहर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों जेल में बंद चिन्मय दास से मिलने पहुंच थे। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

अल्पसंख्यकों पर कोई सुनियोजित हमला नहीं हुआ- बांग्लादेश

उधर, बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्हें विशिष्ट आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया है। देश में अल्पसंख्यकों पर कोई सुनियोजित हमला नहीं हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और जेनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बांग्लादेश के दूत एवं स्थायी प्रतिनिधि तारिक मोहम्मद अरिफुल इस्लाम ने कहा, हम बेहद निराशा के साथ यह कहते हैं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ वक्ताओं ने गलत रूप में लिया है, जबकि वास्तव में उन्हें विशिष्ट आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। हमारी अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। इस्लाम ने 28-29 नवंबर को जेनेवा में अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के मंच के 17वें सत्र के दौरान यह बयान दिया।

इस्कॉन ने चिन्मय दास के समर्थन में जारी किया बयान

इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसायटी (इस्कॉन) ने शुक्रवार को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के समर्थन में एक बयान जारी किया। इसमें कहा कि इस्कॉन इस मामले में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के अधिकारों का समर्थन करता है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस्कॉन ने कभी भी चिन्मय कृष्ण दास प्रभु से खुद को अलग नहीं किया है।

यह बयान संगठन की ओर से उस समय आया है, तब इस्कॉन बांग्लादेश ने गुरुवार को चिन्मय कृष्ण दास प्रभु से खुद को अलग कर लिया था। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा था कि चिन्मय कृष्ण दास के कृत्य संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उन्हें अनुशासनहीनता के कारण संगठन से हटा दिया गया था। हालांकि, इस्कॉन ने अपने एक ताजा बयान में कहा कि वह चिन्मय कृष्ण दास से खुद को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु सगंठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे। इस्कॉन ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि चिन्मय बांग्लादेश में इस्कॉन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा (हिंदुओं के) अधिकारों और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए किए गए आह्वान का समर्थन करते हैं।

संभल की जामा मस्जिद में अवैध निर्माण..

संरचना में फेरबदल, कमेटी ने कई बार सर्वे से रोका

चंदौसी (संभल)। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में एएसआई ने अपना जवाब दे दिया है, जिसमें कई बार मस्जिद कमेटी की ओर से एएसआई की टीम को सर्वे से रोकने का जिक्र है। वहीं डीएम की ओर से उपस्थित डीजीसी सिविल प्रिंस शर्मा ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुबह से ही पुलिस बल न्यायालय व उसके आसपास के क्षेत्र सक्रिय रहा।

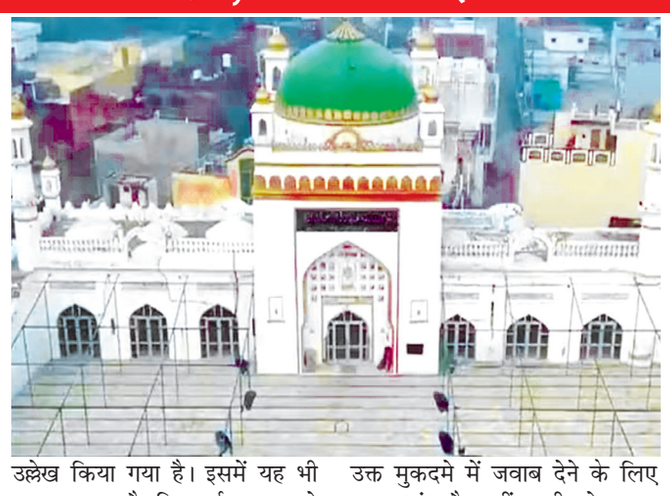

न्यायालय में यूनियन ऑफ इंडिया प्रतिवादी संख्या दो, डायरेक्टर जनरल एएसआई प्रतिवादी संख्या तीन, आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) प्रतिवादी संख्या चार की ओर से शुक्रवार को अधिवक्ता विष्णु शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उनके जवाब में समय-समय पर एएसआई द्वारा विवादित स्थल का सर्वे करने का उल्लेख है। वहीं कई बार मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे की टीम को सर्वे करने से रोका, उसका जिक्र भी जवाब में शामिल है।

इस जवाब में जामा मस्जिद के केंद्रीय संरक्षित स्मारक होने का भी उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ष 1920 से विवादित स्थल एएसआई के संरक्षण में था। एएसआई द्वारा कहा गया है कि मस्जिद के संरचना (स्ट्रेक्चर) में फेरबदल किया गया है। एएसआई द्वारा वर्ष 2018 में जामा मस्जिद कमेटी के विरुद्ध पुरातत्व स्थल पर अवैध रूप से स्टील की रेलिंग लगा कर संरचना में परिवर्तन करने की एफआईआर भी कराई गई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल प्रिंस शर्मा जो जिला मजिस्ट्रेट की ओर से उपरोक्त मुकदमे में पहले दिन ही उपस्थित हो चुके हैं, उन्होंने उक्त मुकदमे में जवाब देने के लिए समय मांगा है। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद की ओर से नियुक्त अधिवक्ता शकील अहमद वारसी व कासिम जमाल न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उन्होंने दावे की नकल मांगी। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि आठ जनवरी 2025 तय कर दी।

हमने न्यायालय से दावे की कॉपी की मांग की है। दावे की कॉपी मिलने पर यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाती है तो जामा मस्जिद की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।

- शकील अहमद वारसी, अधिवक्ता जामा मस्जिद

जामा मस्जिद की ओर से जवाब देने के लिए हम सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसकी हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर आदेश का पालन किया जाएगा।

-कासिम जमाल, अधिवक्ता जामा मस्जिद

मैंने यूनियन ऑफ इंडिया, आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। हमने अपनी बात अपने जवाब व फोटो के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखी है। कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

- विष्णु शर्मा, अधिवक्ता यूनियन ऑफ इंडिया

शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। जिससे कोर्ट से समय मांगा गया। कोर्ट ने दस दिन का समय दे दिया है। समय अवधि के भीतर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।

- रमेश सिंह राघव, कोर्ट कमिश्नर

वोक्कालिगा मठ के संत के खिलाफ प्राथमिकी

चन्नापटना। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आगाह किया कि कर्नाटक में आने वाले दिनों में अराजकता की स्थिति होगी। उन्होंने मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के पक्ष में बयान देने के लिए वोक्कालिगा मठ के एक संत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जनता दल (सेक्युलर) नेता ने संत के खिलाफ प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके खिलाफ नस्ली टिप्पणी करने वाले एक मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। विश्व वोक्कालिगा महासमस्ताना मठ के द्रष्टा कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामी के खिलाफ वक्फ संपत्तियों के विवाद के मद्देनजर यह बयान देने के लिए मामला दर्ज किया गया था कि एक कानून लाया जाना चाहिए, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के पास मतदान का अधिकार न हो। हालांकि, स्वामी ने बाद में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था और इसे जुबान फिसलने का मामला बताया था। कुमारस्वामी ने सवाल किया, उन्होंने (सरकार ने) एक मामला दर्ज किया है और संत को जल्दबाजी में नोटिस दिया गया है, लेकिन क्या उन्होंने उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की है या नोटिस जारी किया है, जिसने मेरे खिलाफ नस्ली टिप्पणी की थी? कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चन्नापटना में संवाददाताओं से मुखातिब जद(एस) नेता ने कहा, ऐसे फैसले लेने से आने वाले दिनों में राज्य में अराजकता फैल जाएगी। बस देखते रहिए।

राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। उप मुख्यमंत्री

तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख समाचार

महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को

मुंबई। एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का एलान हो गया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पांच दिसंबर को शाम पांच बजे आजाद मैदान मुंबई में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि अभी महायुति ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए एक हफ्ता हो चुका है लेकिन सरकार गठन को लेकर कवायद नहीं हुई है। पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह ने महायुति नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन वह टल गई। उधर, विपक्ष लगातार नई सरकार के गठन को लेकर सवाल उठा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का एलान कर दिया।

मुख्यमंत्री भाजपा और उप मुख्यमंत्री बाकी दो सहयोगी दलों से होंगे

पुणे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अब एक हफ्ता हो चुका है लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बरकरार है। इस बीच, कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में सरकार के गठन पर शनिवार को कहा कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि महायुति सरकार बनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे और उप मुख्यमंत्री बाकी दो सहयोगी दलों से होंगे। अजित पवार ने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है जब सरकार गठन में देरी हो रही है। अगर आप 1999 को याद करें तो उस समय भी सरकार बनाने में एक महीने का वक्त लगा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। इन नतीजों में महायुति ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें हासिल कीं। भाजपा ने सबसे अधिक 132 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीतीं और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं। इसके अलावा पांच सीटें महायुति में शामिल अन्य दलों- जन सुराज्य शक्ति (2), राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी (1) और राष्ट्रीय समाज पक्ष (1) ने जीतीं।

पार्टी नेता ने प्रदेश अध्यक्ष नाना को बताया आरएसएस का एजेंट

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर आरएसएस एजेंट होने का आरोप लगाने वाली टिप्पणी पर नागपुर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार हृषिकेश उर्फ बंटी शेल्के को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शनिवार को जारी नोटिस में शेल्के से दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है कि कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी और पटोले को बदनाम करने के लिए उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 28 नवंबर, 2024 को कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवारों की बैठक के बाद की गई शेल्के की टिप्पणियों ने पार्टी के भीतर चिंता पैदा कर दी है। शेल्के विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रवीण दटके से हार गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी हार के लिए पटोले को दोषी ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने तोड़फोड़ और पार्टी के समर्थन की कमी का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए शेल्के ने कहा कि पटोले को कांग्रेस से बर्खास्त कर आरएसएस में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य उनके एजेंडे के अनुरूप हैं। पूर्व नगरसेवक ने आगे पटोले पर उनके अभियान को कमजोर करने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका विरोध करने वाले ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्त किया गया.

मस्जिद सर्वे का कांग्रेस ने किया विरोध

नई दिल्ली। संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को लेकर शनिवार को बड़ा दावा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर 2022 में पूर्व सीजेआई ने मौखिक टिप्पणियां की थीं। इसके चलते ही संभावनाओं का पिटारा खुला है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में 1991 में राज्यसभा में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को लेकर हुई बहस को भी याद किया। उन्होंने उस वक्त राज्यसभा में उत्तर प्रदेश जनता दल के सांसद और लेखक राजमोहन गांधी के भाषण को भी साझा किया। रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा ने एक विधेयक पर बहस की जो पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 बन गया। हाल ही में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के कारण यह इन दिनों बहुत चर्चा में है। 20 मई 2022 को भारत डी वाई चंद्रचूड़ ने तब से एक भानुमती का पिटारा खोल दिया है।

भोपाल गैस त्रासदीः बीमार लोगों को अधिक मुआवजे देने याचिका दायर

भोपाल। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कैंसर और किडनी विकारों से ग्रस्त पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। दो और तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव के बाद कुल 5,479 लोग मारे गए थे और पांच लाख से अधिक लोग शारीरिक रूप से प्रभावित हुए थे। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन' की रचना ढींगरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, पीड़ितों को दिए गए मुआवजे में हुए अन्याय को दूर करने के लिए दो दिन पहले याचिका दायर की गई है। हमें उम्मीद है कि इस पर तीन दिसंबर को सुनवाई होगी, जो भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि याचिका में कैंसर और किडनी की बीमारियों से पीड़ित उन लोगों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है, जिनके स्वास्थ्य को गैस के संपर्क में आने से हुए नुकसान को गलत तरीके से अस्थायी श्रेणी में रखा गया है। ढींगरा ने आरोप लगाया, यूनियन कार्बाइड के अपने दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'मिथाइल आइसोसाइनेट' के संपर्क में आने से स्वास्थ्य को होने वाली क्षति स्थायी प्रकृति की है।

एएसआई ने माना संभल की मस्जिद के स्वरूप से हुई छेड़छाड़

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिला अदालत में शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपना जवाब पेश किया। एएसआई ने कहा कि विवादित स्थल 1920 से उनके संरक्षण में है। एएसआई द्वारा समय-समय पर केंद्रीय संरक्षित स्मारक के सर्वे की कोशिशों में मस्जिद कमेटी ने रुकावट डाली। इसके साथ ही मस्जिद की संरचना में बदलाव भी किया गया है।

संभल में मस्जिद का कानूनी विवाद क्या है?

दरअसल, 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश चंदौसी में संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया था जिसमें दावा किया गया था कि 1529 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका 19 नवंबर को ही दायर की गई थी और उसी दिन न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में संभल कोर्ट में कुल आठ याचिकाकर्ता हैं। इनमें वरिष्ठ वकील हरि शंकर जैन भी शामिल हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ विवाद में भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने वाद दाखिल किया है। संभल के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी इसमें चर्चित याचिकाकर्ता हैं।

इस मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

ने दावा किया कि संभल में हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बना दी गई। जैन ने दावा किया कि इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसका जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष भी यही बात कही गई है ताकि हरिहर मंदिर का सच सामने आ सके। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहा, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार इसी जगह पर होगा। इसलिए यह स्थान पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल है।

विवाद में एएसआई का क्या रुख है?

शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में शुक्रवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में प्रतिवादी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अपना लिखित हलफनामा दाखिल किया। एएसआई की ओर से अधिवक्ता विष्णु शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। इस जवाब में जामा मस्जिद के केंद्रीय संरक्षित स्मारक होने का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ष 1920 से विवादित स्थल एएसआई के संरक्षण में था। एएसआई द्वारा कहा गया है कि मस्जिद की संरचना में फेरबदल किया गया है। अवैध रूप से स्टील की रेलिंग लगा कर संरचना में बदलाव करने की एफआईआर भी कराई गई थी। जवाब में यह भी कहा गया कि समय-समय पर एएसआई द्वारा विवादित स्थल का सर्वे किया गया और कई बार मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे की टीम को सर्वे करने से रोका। एएसआई ने अदालत को बताया कि स्मारक/मस्जिद की मौजूदा स्थिति ज्ञात नहीं है, क्योंकि मस्जिद समिति के सदस्यों ने एएसआई अधिकारियों को %लंबे समय से% मस्जिद में प्रवेश करने से रोका है। हालांकि, एएसआई ने दावा किया कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनकी टीम ने जिला प्रशासन की सहायता से जब भी संभव हो, स्मारक का निरीक्षण किया।

हलफनामे में 25 जून 2024 की एक निरीक्षण रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक की मूल संरचना कई स्थानों पर विकृत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य भाग के अंदरूनी हिस्से में चमकीले रंगों का भरपूर इस्तेमाल किया गया और स्मारक का समग्र स्वरूप काफी खराब हो गया।

क्या होता है केंद्रीय संरक्षित स्मारक?

भारत में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से जुड़ा एक कानून है जिसे %प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम में स्मारक की परिभाषा दी गई है जिसमें प्राचीन स्मारक के अवशेष या स्थल भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 1958 के कानून के अंतर्गत 3600 से ज्यादा स्मारकों और स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है जिनमें से एक संभल की जामा मस्जिद भी है। एएसआई के अनुसार, जब किसी प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने पर उसे संरक्षित स्मारक कहा जाता है।

1958 के अधिनियम के तहत कम 100 साल से अस्तित्व में होने वाली कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई टीला या दफनाने की जगह, या कोई गुफा, चट्टान की मूर्ति, शिलालेख या मोनोलिथ (जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का हो) प्राचीन स्मारक हो सकती है।

सरकार किसानों से धान नहीं खरीदने का कर रही है षडयंत्र : मंडावी

■ कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला

बीजापुर। बीजापुर में कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वह किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 160 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है. इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति दिन सरकार को लगभग साढ़े तीन लाख मिट्रिक टन की खरीदी प्रति दिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है। उसमें लक्ष्य प्राप्त करना असंभव लग रहा। विधायक ने आगे कहा कि सोसाइटियो को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिये उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है।

सरकार ने यह घोषणा किया है कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आयेगा, लेकिन जो लोग 14 नवंबर को धान बेचे थे, उनके खाते के रकम नहीं आया है, जो रकम आ रहा है। वह एक मुस्त 3100 नहीं है। सिर्फ 2300 रू. प्रति क्विंटल ही आ रहा है। जो समर्थन मूल्य है उतना अनावरी रिपोर्ट गलत बनाया जा रहा। जिसके आधार पर मात्र 9 से 12-14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा। किसानो से पूरा 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बीज उत्पादक किसानों से सोसायटी में धान नहीं खरीदा जा रहा। सोसायटी में सूचना चस्पा किया गया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जायेगा। वही उन्होंने बारदानों को लेकर कहा कि सोसायटी में बारदाना की कमी है। किसान परेशान है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बरदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। धान खरीदी केन्द्रो में टोकन नहीं जारी किया जा रहा है।किसान घंटो खड़े रहते है। आनलाईन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन बाद का भी टोकन नही मिल रहा है। विधायक ने कहा कि धान की कीमत का भुगतान 3217 रू. में करे क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़ाकर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी किया था। धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बफ स्टॉक के उठाव की नीति को बदल दिया है। पहले इस प्रावधान के होने से समितियों के पास ये अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनोती दे सकें।

अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद बफ स्टॉक के उठाव की कोई सीमा ही नहीं है। धान खरीदी केन्द्रो में जगह की कमी आ रही है। पहले मार्कफेडे द्वारा समस्त धान का निपटान 28 फरवरी तक कर देने की बाध्यता रखी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। जबकि धान खरीदी 31 जनवरी तक होगी उसके बाद धान खरीदी बंद हो जाएगी, यानी समितियों, संग्रहण केंद्रों में धान अब दो महीने तक रखा रह रहेगा। विधायक ने आगे कहा कि धान मिलिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रति क्विंटल 120 रुपए देने का निर्णय लिया था जिसका परिणाम यह हुआ था कि प्रदेश भर में 700 नई राइस मिलें खुली थीं। अब सरकार ने मिलर के लिए 120 रुपए को घटाकर 60 रुपए कर दिया है। इस कारण राईस मिलर हड़ताल पर है धान सोसायटी में जाम है। मिलरों को 120 की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मीलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं।

मोहन मरकाम ने धान खरीदी में षडयंत्र का लगाया आरोप

कोंडागांव। कोंडागांव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार पर धान खरीदी में षडयंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदी कम करने की साजिश कर रही है। इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, लेकिन केवल 47 दिनों में इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। समितियों को प्रति दिन 752 क्विंटल की सीमा दी गई है, जिससे किसानों को धान बेचने के लिए बार-बार तारीख लेनी पड़ रही है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम से 15 दिनों बाद का टोकन मिल रहा है, और भुगतान में भी देरी हो रही है। किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए के बजाय 2300 रुपए ही मिल रहे हैं। सोसायटियों में बारदाने की कमी और बफर स्टॉक नीति में बदलाव से धान खरीदी बाधित हो रही है। मिलरों को प्रति क्विंटल 120 रुपये के बजाय 60 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे मिलिंग कार्य प्रभावित है। पूर्व मंत्री ने सरकार से धान का समर्थन मूल्य 3217 रुपए करने की मांग की और कांग्रेस की पुरानी नीति को बेहतर बताते हुए किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील की।

ग्रामीण महिलाओं के पहल पर ग्राम पंचायत गारावण्डकला ने मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली बंद किया

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत गारावण्डकला के पुजारीगुड़ा पारा के सप्ताहिक बाजार में मुर्गा लड़ाई (स्थानिय बोली में कुकड़ागाली) का बाजार लंबे समय से लगता आ रहा है, वर्तमान में इस क्षेत्र में मुर्गा लड़ाई बाजार के साथ शराब और जुआ का प्रचलन भी अधिक बढ़ते देख एवं आस-पास क्षेत्र में भय, गंदगी की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत के सभी महिला संगठन समूह के द्वारा ग्राम पंचायत गारावण्डकला में मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली को पूरी तरह से बंद करने हेतु आवेदन दिया गया।

आवेदन में ग्राम पंचायत के सभी महिला संगठन के द्वारा कहा गया कि मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली में ग्रामीणों द्वारा शराब पीकर महौल खराब करने एवं आसपास गंदगी फैलाये जाने लगा है। गांव में शराबियों के द्वारा शराब की बोतल फोड़ कर गांव में दहशत फैलाने का प्रयास किया जाता है, जिससे महिलाओं एवं बच्चों में दहशत का माहौल व्याप्त है। महिलाओं की जायज मांग को देखते हुए ग्राम पंचायत गारावण्डकला की ग्राम सभा में पुजारीगुड़ा पारा में मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली को बंद करने आदेश जारी किया गया है । इसके साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा अधिनस्त थाना को इससे अवगत करवाते हुए इस संबंध में सरपंच ने पुजारीगुड़ा में मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली जुआ-शराब बंद होने की जानकारी आस-पास के इलाके में फैला दिया गया है, यदि बिना पंचायत के अनुमति के मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली संचालित किया जाता है तो सख्त कार्यवाही किया जायेगा ।

उल्लेखनिय है कि बस्तर संभाग के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ मुर्गा लड़ाई अब विक्रित होकर खुले खाम जुआ और शराब के कारेबार में बदल गया है। यह एक प्रकार का ऐसा जुआ है, जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा मुर्गे के पैर में धारदार चाकू बांधकर इनको आपस में लड़ाकर दाव लगाया जाता है, जिसमें एक मुर्गे की मौत हो जाती है, जीतने वाला जश्न मनाता है। जितने वाला मरे हुए मुर्गे को अपने कब्जे में लेकर मुर्गा में लगाये गये सभी रकम उसकी हो जाती है, बस्तर के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई अब विक्रित हो गया है कि इसमें खुले आम लाखों रूपये के दांव लगाने के लिए गांव में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा लगने लगा है। इसके साथ ही यहां खुलेआम शराब, खुडखुड़ी एवं खाने-पीने का बाजार लगने लगा है।

ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई की परंपरा के नाम पर शराब और जुए का बाजार में परिर्वतित हो गये, इस बाजार में लोगों के मध्य विवाद होने लगे हैं, कई बार शराब के नशे में विवाद के दौरान हत्या तक होने लगी है। ग्रामीणों की जागरूकता एवं पंचायत के इस निणर्य की आस-पास के ग्रामों में भी सराहना की जा रही है।इसका अनुसरण अन्य ग्रामीण इलाको में भी करने के लिए प्रसाशन को पहल कर विक्रत हो चुकी मुर्गा लड़ाई-कुकड़ागाली की परंपरा के नाम पर शराब और जुए का बाजार पर अंकुश लगाने के लिए जनजागरूकता की अवश्यकता है।

किसान बनकर धान खरीदी केंद्र पहुंचे कलेक्टर किसानों की परेशानी से हुए अवगत

अंबिकापुर। सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपन किसान के भेस में सीतापुर के पेटला स्थित धान खरीदी केंद्र पहुंच कर धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया एवं किसानों को होने वाले परेशानी से भी अवगत हुए। कलेक्टर ने पेटला धान उपार्जन केंद्र, समिति प्रबंधकों को चेतावनी दी कि काम में की लापरवाही तो होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर ने सहकारी बैंक में भी किसान के साथ घंटो लाइन में लगकर पैसे निकाले और बैंकिंग व्यवस्था देखा।

कलेक्टर विलास भोसकर सीतापुर एसडीएम रवि राही के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर धान खरीदी केंद्र पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लाइन में लगकर टोकन प्रक्रिया का अवलोकन किया। कलेक्टर भोसकर लगभग 1 घण्टे पूरे खरीदी केंद्र का भ्रमण करते रहे। समिति प्रबंधक, कर्मचारियों सहित खरीदी केंद्र में उपस्थित किसी ने भी कलेक्टर को इस रूप में नहीं पहचाना। उन्होंने किसानों के साथ कर्मचारियों के व्यवहार का भी आकलन किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी बात की। वहीं फड़ में धान की तौलाई करवाकर, तौल पत्रक की पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब सभी को बताया गया कि यह जिले के कलेक्टर विलास भोसकर हैं तो सभी भौचक रह गए। कलेक्टर श्री भोसकर ने समिति प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसका ध्यान रहे। पूरी धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान चौकन्ने रहें, कोचियों-बिचौलियों पर निगरानी रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। धान खरीदी के निरीक्षण के पश्चात कलेक्टर भोसकर सहकारी बैंक सीतापुर पहुंचे। धान बेचने के पश्चात पैसे निकालने लाइन में लगभग एक घंटे तक लगे रहे,तब भी कलेक्टर को किसानों ने नहीं पहचान पाया। कलेक्टर लाइन में लगकर पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने एक किसान के खाते से पैसे निकालकर गिनकर देखा। उन्होंने नया पासबुक बनाने हेतु फॉर्म लिया तथा इसके सम्बन्ध में जानकारी ली। निरीक्षण पश्चात कलेक्टर श्री भोसकर ने किसानों से चर्चा करते हुए बैंक की व्यवस्थाओं के सम्बंध में फीडबैक लिया तथा समस्या के सम्बंध में पूछा। उन्होंने शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया कि धान बेचने के उपरांत किसानों के खाते में राशि के अंतरण या अन्य बैंकिंग कार्य में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि कर्मचारियों का व्यवहार किसानों के प्रति अच्छा रहे और उन्हें खरीदी केंद्रों में और पैसा निकालने में कोई परेशानी ना हो।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भोपालपटनम बालक आश्रम के बच्चे चक्कर खाकर गिरने लगे

बीजापुर। जिले के भोपालपटनम स्थित बालक आश्रम शाला में 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय घटी जब बच्चों ने शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे, इसी दौरान अचानक से पांच-छह बच्चे चक्कर खाकर गिर पड़े, और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी चक्कर खाने लगे। शाला प्रबंधन को आशंका है कि आश्रम में भूत-प्रेत की कोई अदृश्य शक्ति की वजह से बच्चे अचनक बीमार हो गए, हालांकि बच्चों को आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनका झाड़-फूंक भी कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार के आधी रात के समय स्थिति बिगडऩे पर आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों को चक्कर आने का कारण हिस्टेरिया और डर हो सकता है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की स्थिति अब स्थिर है, और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अस्पताल में इलाज के बाद भी आश्रम में कुछ लोग भूत-प्रेत का शक जता रहे हैं।

रेत माफिया ने जब्त हुई गाड़ियों को किया गायब

जांजगीर चांपा। अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन और खनिज विभाग विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों प्रशासन के निर्देश पर खनिज विभाग ने महानदी के देवरघटा में रेड किया। रेड के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले गाड़ियों को जब्त किया। घटना के बाद खनिज माफिया के गुर्गों ने सील तोड़कर सीज की गई गाड़ी को मौके से गायब कर दिया। खनिज विभाग की टीम अब गायब चैन माउंटेन गाड़ी की तलाश कर रही है। तलाशी के दौरान एक गाड़ी खनिज विभाग को मिल गई है दूसरे की तलाश जारी है। खनिज विभाग के मुताबिक जिले में रेत घाटों का ठेका नहीं हुआ है। बावजूद इसके बिना रायल्टी चुकाए अवैध रेत का खनन जारी है। बिलासपुर और रायपुर के रेत माफिया यहां एक्टिव हैं। खनिज विभाग भी लगातार अवैध रेत खनन के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम ने दो चेन माउंटेन को जब्त किया था। जब्त किए गए गाड़ियों को माफिया के लोग सील तोड़कर ले गए।

16 लाख की सीसी रोड सात महीने में उखड़ी

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत गांव के विकास के नाम पर चलाई गई योजनाओं का हाल बेहद बुरा है। खड़गवां जनपद के ग्राम पंचायत मंगोरा में 16 लाख रुपए की लागत से बनीं सीसी रोड 8 महीनों में ही उखड़ गई।जिससे अब सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क को लेकर अब सरपंच और सचिव के साथ निरीक्षण करने वाले एसडीओ और इंजीनियर की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मंगोरा गांव के लोगों के मुताबिक सड़क निर्माण में किसी भी तरह के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।जिसके कारण ही एक बारिश भी सड़क नहीं झेल पाई।अब इस सड़क पर बालू और गिट्टी उखड़कर बिखर रहे हैं। सरकार गांव का विकास चाहती है, लेकिन सरपंच और सचिव के साथ अधिकारी ही योजनाओं को बर्बाद कर रहे हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण अजय सिंह ने कहा ग्राम पंचायत के मद से सड़क का निर्माण करवाया गया था। लेकिन सड़क कुछ ही महीने में उखड़ने लगी है।

8 करोड़ की ठगी, ब्रांच मैनेजर समेत 3 आरोपी हुए गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। लुभावने बिजनेस स्कीम का झांसा देकर महिला समूहों को ठगी का शिकार बनाने वाले फ्लोरा मैक्स का मकड़जाल जांजगीर-चांपा में भी फैला हुआ है, जहां 2700 लोगों को 30-30 हजार रुपए को झांसा देकर कुल लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मामले में जांजगीर पुलिस ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया नीरा साहू की ठगी की शिकायत पर चांपा पुलिस ने अलग-अलग जगहों छापेमारी कर कोरबा निवासी आरोपी ईश्वर दास महंत, जांजगीर-चांपा जिला निवासी संतोष दास मानिकपुरी और सक्ती जिला निवासी गोपी किशन सुखसारथी को पकड़ा। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए लगभग 10-10 लाख रुपए लेना स्वीकार किया। आरोपियों के साथ कार्यालय से उपयोग किए कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, लेपटाप, नोट गिनने का मशीन, रजिस्टर और प्रचार-प्रसार की सामग्री बरामद किया है। शिकायकर्ता नीरा साहू ने चाम्पा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर छापामार कार्रवाई

जांजगीर चांपा। धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर खाद्य, राजस्व एवं मंडी विभाग के संयुक्त दल ने अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण करने वाले के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की और 30 क्विंटल धान और 10 क्विंटल चावल जब्त किया। फूड ऑफिसर कौशल साहू ने बताया कि वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम पंचायत केरा के व्यापारी मनीष ट्रेडर्स के संचालक मनीष केशरवानी के गोदाम से 76 बोरी धान वजन 30.40 क्विंटल जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मारूति किराना स्टोर केरा रोड जांजगीर से खाद्य विभाग की टीम ने 24 बोरी में कुल 9.51 क्विंटल चावल जब्त किया। छत्तीसगढ़ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 का उल्लंघन करने के कारण संबंधित आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त जांच टीम में सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, एसडीएम जांजगीर ममता यादव भी शामिल थे।

अवैध रेत भंडारण पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई

■ 72 टिप्पर रेत जब्त, 30 इमारती पेड़ भी काटे

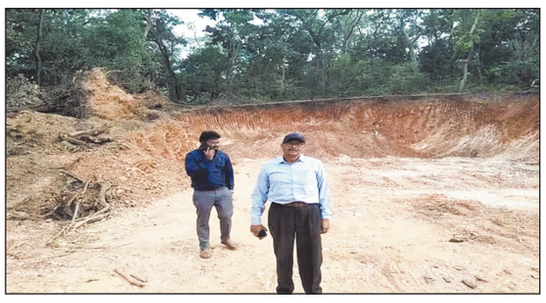

बीजापुर। बीजापुर जिले के तारलागुडा गोदावरी नदी के किनारे चल रहे अवैध रेत भंडारण के खिलाफ भोपालपटनम एसडीएम व तहसीलदार ने कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 72 टिप्पर अवैध रेत जप्त किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम यशवंत नाग और तहसीलदार लक्ष्मण राठिया ने अचानक निरीक्षण करते हुए इस मामले पर कार्रवाई की। मौके पर मौजूद सरपंच पति भास्कर काका ने स्वीकार किया कि पट्टा प्राप्त भूमि स्वामी काका राजन ने अपनी भूमि पर समतलीकरण कर उस पर 72 टिप्पर रेत का भंडारण किया गया था।

वन विभाग के बीट गार्ड शैलेश लम्बाड़ी और शैलेन्द्र एट्टी ने बताया कि समतलीकरण के दौरान लगभग 30 बड़े पेड़ों को काटा गया था, जिनमें साजा, तेंदू, मोयन, और सागौन जैसे पेड़ शामिल थे। ये पेड़ गिराकर उनकी बलि चढ़ाई गई थी। इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया है और कटे पेड़ों को लेकर कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने अवैध रेत भंडारण को सील कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। इसके अलावा बिना अनुमति रेत का भंडारण के साथ बड़े वृक्षों की कटाई और अवैध मुरुम उत्खनन का निरिक्षण किया गया है। उसमें संबंधित के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जा रही है। हालांकि, यह सवाल उठ रहा है कि जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है, जबकि संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा हैं। नदी किनारे अवैध भंडारण कर करोड़ों का माल पार हो रहा है।

भाजपा ने भी खोला मोर्चा

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं ने वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और बस्तर सांसद महेश कश्यप से मुलाकात कर अवैध रेत खनन को तत्काल रोकने की मांग की है।

नारायणपुर-कुतुल मुख्य मार्ग से 3 आईईडी बरामद

नारायणपुर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में लगातार क्षेत्र में सघन नक्सल उन्मूलन माड़ बचाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर से आज शनिवार को डीआरजी एवं बीडीएस के संयुक्त बल नक्सल उन्मूलन अभियान पर माड़ क्षेत्र की ओर रवाना हुऐ थे। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा नारायणपुर-कुतुल मुख्य मार्ग पर 5 किलो से अधिक वजनी वाले 3 आईईडी को सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए बरामद कर तीनों आईईडी. को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया।

नक्सलियों द्वारा लगाये गये आईईडी आदिवासी ग्रामीणों एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नीयत से लगाया गया था। सुरक्षा बलों की सजगता और सतर्कता से आईईडी को बरामद कर निष्क्रिय कर नक्सलियों के नापाक इरादों को विफल कर दिया है। उक्त कार्यवाही में डीआरजी एवं बीडीएस टीम का योगदान रहा । उल्लेखनिय है कि इससे पूर्व वर्ष 2024 में नक्सलियों द्वारा लगाये गये आईईडी से 20 से अधिक निर्दोष ग्रामीण मारे गये या गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

पुलिस कैम्प से भयभीत नक्सलियों ने महिला नक्सली ममता को गिरफ्तार कर लपता करने का लगाया आरोप

कांकेर। नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजनल कमेटी के सचिव सुखदेव कौड़ो ने जारी प्रेस वक्तव्य में कहा है कि बुजुर्ग, बीमारी से झूज रही महिला नक्सली डीव्हीसीएम ममता उम्र 58 वर्ष ने कुछ दिनो से गंभीर बीमार की वजहे से कांकेर जिले के सितरम गांव में रुकी थी। 12 नवम्बार को पुलिस ने आधी रात को घर का घेराव कर ममता को गिरफ्तार करके लपता कर दिया है, जिसे तत्काल अदलात में पेश कर इलाज करवाने की मांग की है।नक्सली संगठन ने यह स्वीकार किया है कि नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने के नाम पर जंगल, नदी-नाला एवं गांव बस्ती को पुलिस छावनी बनाकर पुलिस कैम्प बिठाकर पुरा इलाका को भयभीत कर रखे है। इस फासीवादी दमन को उत्तर बस्तार डीविजनल कमेटी खंडान करती है।

संक्षिप्त समाचार

खमतराई में 64 लाख के विकास प्रोजेक्टर का मूणत ने किया भूमिपूजन

रायपुर। पश्चिम विधानसभा में पश्चिम

विधायक राजेश मूणत लगातार विकास कार्यों में जुटे हुए है। इसी के तहत शनिवार को वीर शिवाजी वार्ड के अंतर्गत आने वाले खमतराई के लोगों को सड़क- नाली और सामुदायिक भवन के विस्तार के लिए 64 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन स्थल पर मौजूद नगर निगम अधिकारियों से कहा कि जितने भी काम शुरू हुए हैं, सभी समय पर पूरे होंगे तो लोगों को जल्दी सुविधा मिलेगी। इनमें खमतराई बाजार के दोनों ओर 24 लाख रुपये से चौड़ी नाली बनाई जाएगी। खमतराई सामुदायिक भवन के दूसरे माले का निर्माण कार्य मंजूर करवाया और फिलहाल 10 लाख रुपए का फंड अलाट किया है। वार्ड के नीम डबरी इलाके में कंक्रीट रोड और नालियों का 17 लाख रुपए का काम और साहूपारा इमली पेड़ के पास सीसी रोड और नाली के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए के काम का भूमिपूजन भी कर दिया।

फ्लाई बिग एयरलाइन 19 से शुरु करेगा अंबिकापुर-बिलासपुर के बीच हवाई सेवा

रायपुर। 19 दिसंबर से अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच छह घंटे का सफर अब केवल एक घंटे में पूरा होने वाला है क्योंकि फ्लाई बिग एयरलाइन 19 दिसम्बर से अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच हवाई सेवा शुरु करने जा रही है। यह सेवा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मिलेगा। फ्लाई बिग एयरलाइन ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 19 दिसंबर से वे अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच हवाई सेवा शुरु कर रहे है। इसके अनुसार विमान अंबिकापुर से दोपहर 12:50 बजे रवाना हो कर बिलासपुर में 13:45 बजे पहुंचेगा। वापसी में यह फ्लाइट बिलासपुर से 14:10 बजे टेकआफ और 15:05 बजे अंबिकापुर लैंड करेगा। एटीआर श्रेणी का 72 सीटर प्लेन होगा।

नई दिल्ली-बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में मिलेगी एसी-3 की सुविधा

रायपुर। यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने 12442/12441 नई दिल्ली-बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक एसी-3 कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। जो 12442 एक्सप्रेस में नई दिल्ली से 3 दिसंबर से और 12441 एक्सप्रेस में बिलासपुर से 5 दिसंबर से उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ कोटशिला स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग एवं अन्य संरक्षा कार्य के चलते हेतु पावर ब्लॉक लिया जा रहा है इस वजह से 1 से 4 दिसम्बर तक 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 दिसम्बर को 18110/18109 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

163 आईएएस अफसरों में से तीन को मिला छत्तीसगढ़ कैडर

रायपुर। केंद्रीय लोक कार्मिक पेंशन प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यूपीएससी 2023 के चयनित 163 आईएएस अफसरों को राज्य कैडर आवंटित कर दिया है जिनमें छत्तीसगढ़ को तीन अफसर मिले हैं। ये तीनों ही आउटसाइडर केटेगरी से अन्य राज्यों के मूल निवासी हैं। छत्तीसगढ़ को जिन तीन आईएएस अफसरों का कैडर मिला है, उनमें से अक्षय दोशी की यूपीएससी में 75वीं रैंक आई थी, वह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनका सिलेक्शन अनरिजवर्ड कैटेगरी में हुआ है। विपिन दुबे की यूपीएससी में 238वीं रैंक आई थी, वह भी अनरिजवर्ड कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके साथ ही क्षितिज गुरभेले को भी छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट किया गया है, गुरभेले की यूपीएससी में 441वीं रैंक आई थी वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

प्रेस क्लब में जल्द लगेगा आयुष्मान कार्ड शिविर

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा जल्द ही पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का शिविर लगाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने 70 या 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को केवल आधार कार्ड लेकर शिविर में आना होगा। शिविर में न आ पाने की स्थिति में किसी परिजन या परिचित के हाथों आधार कार्ड की छायाप्रति, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ शिविर में भेजना होगा। हालांकि मोबाइल नम्बर उन्हीं का लगेगा, जिसमें ओटीपी आएगा। 70 वर्ष से कम उम्र के प्रेस क्लब सदस्य और परिजनों को आधार कार्ड की छाया प्रति और राशन कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर आना होगा। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि जिन सदस्यों के आधार और राशन कार्ड अपडेट नहीं हैं, वे अपडेट करवा लें, ताकि शिविर में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब अपने सदस्यों की सुविधाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रख रहा है। विगत दिनों प्रेस क्लब में आयोजित ड्रायविंग लाइसेंस शिविर में 300 से अधिक पत्रकार और उनके परिजनों ने लर्निंग लायसेंस बनवाया और अपडेट करवाया। श्री ठाकुर ने कहा की ड्रायविंग लायसेंस का शिविर जल्द ही फिर लगाया जाएगा। जो प्रेस क्लब सदस्य और उनके परिजन किसी कारणवश ड्रायविंग लायसेंस नहीं बनवा पाए, वे अगले शिविर में उसे बनवा सकेंगे।

संगठन चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपाई

अनुराग सिंहदेव ने कहा- छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बनाया 60 लाख सदस्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक हुई। सदस्यता अभियान को लेकर प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 86 दिनों में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया। छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख ऑफलाइन और 45 लाख ऑनलाइन मेंबर बनाए हैं। यह विश्वास का प्रतीक है। यह काम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का प्रमाण है।

संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने कहा, प्रत्येक 10 वर्षों में संगठन का चुनाव होता है और सदस्य की दृष्टि से सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। देश में अब तक 11 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 से 20 तारीख के बीच में बूथों का चुनाव होना था। 24110 बूथों में 15000

बूथों का हो चुका है। 5 तारीख तक सभी बूथों में निर्वाचन होना है। इसके बाद 15 दिसंबर तक मंडलों का निर्वाचन होना है। जिले के चुनाव के लिए 30 तारीख निर्धारित की गई है।

मंडल और जिला अध्यक्ष के लिए उम्र की सीमा निर्धारित

पारख ने बताया, पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि युवा पीढ़ी को सक्रिय करना है। 35 से लेकर 45 वर्ष आयु सीमा के युवाओं को भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाना है। जिले के लिए निर्वाचन में 45 से 60 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है। उनकी टीम में किसी भी उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। एक शर्त यह भी तय किया गया है कि पार्टी का कोई भी मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जरूरी है कि वह पार्टी के किसी न किसी दायित्व में रहा हो। अनुभवी व्यक्ति को ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष के लिए बीजेपी का 6 साल सक्रिय सदस्य रहना अनिवार्य है। बूथ प्रमुखों से चर्चा करके एक नाम फाइनल होगा।

बता दें कि भाजपा संगठन महापर्व कार्यशाला 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। इसमें शामिल होने बीजेपी प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचे हैं। पार्टी प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने बताया कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा की सम्भागस्तरीय बैठकें आहूत की गई हैं। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव, नरेश बंसल राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी ,गजेंद्र पटेल चुनाव पर्यवेक्षक ,उपमुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय व वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया बस संगवारी एप

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस संगवारी एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से बस यात्रियों को सभी [प्रकार की जानकारी घर बैठे मिलेगी। इस एप से बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी मिलेगी। एप में पांच हजार से अधिक बसों की जानकारी मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के

जरिए मिल सकेगा।

परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में सीएम साय को विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ओर से तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस एप में वर्तमान में पांच हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट में संचालित हैं। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

संविधान दिवस की 75 वीं वर्षगाँठ पर रायपुर में बड़ा आयोजन

■ **मेरा संविधान-मेरा अभिमान में युवाओं से संवाद करेंगे सांसद बृजमोहन और राकेश सिन्हा**

रायपुर। भारत के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 100 से अधिक कालेजों में मेरा संविधान-मेरा अभिमान विषय पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है । इस अवसर पर कॉलेज युवाओं को देश के संविधान के महत्व को समझाने और संविधान के सम्मान और सुरक्षा के संकल्प लेने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल के दिशानिर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, इस अभियान के समापन समारोह में 7 दिसंबर,शनिवार को भाजपा के थिंकटैंक और सुप्रसिद्ध विचारक राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा शिरकत करेंगे.समारोह में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा साथ ही देश के संविधान की रक्षा हेतु युवाओं को शपथ भी दिलाई जाएगी. कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने बताया कि देश के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आने

वाले सभी केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थाओं आईआईएम, एनआईटी,ट्रिपल आई टी,एम्स और सिपेट समेत 100 से अधिक कॉलेज़ो में मेरा संविधान-मेरा अभिमान विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है . मेरा संविधान- मेरा अभिमान कार्यक्रम का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे साइंस कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में रखा गया गया है . इसमें भाजपा के थिंकटैंक और सुप्रसिद्ध विचारक राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अनेक वरिष्ठ नेता,अधिकारी शिरकत करेंगे।

राजधानी में रात के अंधेरे में शरारती तत्वों ने आठ गाड़ियों को किया आग के हवाले

रायपुर। राजधानी रायपुर के आरडीए कॉलोनी, बोरियाखुर्द में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक के बाद एक आठ गाड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आगजनी में 7 दो पहिया और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए. आगजनी इतनी भयावह थी कि आग से आस-पास के घर तक जा पहुंची. पीड़ित परिवारों ने जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जताई है. वहीं इस मामले में पीड़ित परिवारों के लोगों ने बताया कि घटना रात करीब 3 बजे की है. जब स्कूटी में ब्लास्ट होने की आवाज़ से कॉलोनीवासियों को आग लगने का पता चला और देखते ही देखते 4 परिवारों के 6 दो पहिया वाहन और एक ऑटो आग की चपेट में आ गए. पीड़ित संतोष सिन्हा, डॉ राजेंद्र साहू और नितिन सिंह ने मामले की शिकायत टिकरापारा थाने में की है. वहीं इस घटना के पीड़ितों ने साज़िश के तहत इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया बीते शाम कॉलोनी में पीड़ितों का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें शिकायत न करने की धमकी भी मिली थी. जिसके बाद ये घटना हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बोरियाखुर्द में देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है. आए दिन अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसके बावजूद इलाक़े में पुलिस गंभीरता से गश्त नहीं करती लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर है. वहीं इस मामले में टिकरापारा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बोरियाखुर्द में गाड़ियों में आग लगने की शिकायत मिली है. शिकायतकर्ताओं ने जान बूझ कर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है. मामले की जांच जारी है।

रायपुर में देर रात शरारती तत्वों ने आठ गाड़ियों को एक के बाद एक किया आग के हवाले

रायपुर। राजधानी रायपुर में शरारती तत्वों ने रात के समय में आठ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अज्ञात लोगों ने आठ खाड़ी बाइक पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। पूरा मामला आरडीए कॉलोनी बोरियाखुर्द की है, जहां बीती रात अज्ञात लोगों ने एक के बाद एक आठ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, आगजनी में सात दोपहिया और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए। आग लगने से सभी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी। आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग उठे और घटना स्थल पहुंचकर देखे। इस दौरान लगभग चार परिवारों के छह दोपहिया वाहन और एक ऑटो आग

की चपेट में आ गया।

वहीं इस मामले में पीड़ित संतोष सिन्हा, डॉ. राजेंद्र साहू और नितिन सिंह ने मामले की शिकायत टिकरापारा थाना में की है। उनका आरोप है कि इस घटना को साज़िश के तहत अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते शाम कॉलोनी में पीड़ितों का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें शिकायत न करने की धमकी भी मिली थी।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि शाम की घटना के बाद ये देर रात घटना हुई है। मामले को लेकर टिकरापारा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बोरियाखुर्द में गाड़ियों में आग लगने की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ताओं ने जान बूझकर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। इस पूरे मामले की जांच जारी है।

सर्व ब्राह्मण समाज युवक -युवती परिचय सम्मेलन की तैयारी को लेकर हुई बैठक

रायपुर। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिसम्बर, रविवार को प्रातः 11 बजे से श्री दूधाधारी सत्संग भवन, रायपुर में होने वाले सर्व ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन की तैयारी बैठक श्री जगन्नाथ मंदिर, टूरी हटरी, पुरानी बस्ती में हुई। बैठक में अब तक आये लगभग 350 पंजीयन और प्राप्त हो रहे नवीन पंजीयन, अतिथि स्वागत, मिलन-2024 स्मारिका विमोचन, युवक-युवतियों का परिचय, भोजन व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा कर कार्यभार तय किया गया। ज्ञात हो कि सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ,विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा , नपानि सभापति श्री प्रमोद दुबे , नपानि लोनिवि अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा , भाजपा पार्षद दल प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे , समाजसेवी श्री राजीव वोरा ने आतिथ्य हेतु अपनी

सहमति प्रदान कर चुके हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा, कार्यक्रम संयोजक नितिन कुमार झा, स्मारिका सम्पादक रज्जन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सचिव सुरेश मिश्रा, प्रदेश महासचिव अजय अवस्थी, महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा, मिथिलेश रिछारिया, विद्या भट्ट, बबीता मिश्रा, सुमन पाण्डेय, प्रीति मिश्रा, सतीश शर्मा, राघवेन्द्र पाठक, उमेश शर्मा, रवि शर्मा, वीणा मिश्रा, सुरभि शर्मा, कल्पना मिश्रा, अनिता राव सहित काफी संख्या में विप्रजन उपस्थित थे।

मकान लेने के लिए फटाफट बनवा लें डॉक्यूमेंट्स, सरकार ने बढ़ाई डेटलाइन

रायपुर। अपना आशियाना लेने का सपना देख रहे लोगों के लिये खुशखबरी है। ऐसे लोग जिनके पास मकान लेने के लिये जरूरी दस्तावेज अभी तक नहीं बन पाये हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने उन्हें समय दिया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वर्तमान में जारी सर्वेक्षण के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उनके आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करते हुए उन्हें दस्तावेजों के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य

दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया है।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज इत्यादि की प्रविष्टि भारत सरकार की ओर से अनिवार्य की गई है। उप मुख्यमंत्री साव को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से यह पता चलने पर कि वांछित दस्तावेजों में से मुख्यत: राजस्व संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है। साव ने हितग्राहियों की असुविधा को देखते हुए और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करते हुए सभी नगरीय निकायों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) में प्राप्त हो रहे आवेदनों में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त न करते हुए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए यथोचित समयावधि प्रदान करने को कहा है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव जिला- कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)
Email - ID: ee-res.kondagaon@nic.in, Fax & Ph. No.-07786-242243

मैनुअल पद्धति वर्ष 2024-25 हेतु सूचना क्रमांक-24 (प्रथम दौर)
जोनल निविदा आमंत्रण

क्रमांक/24/व.ले.लि./नि.प्र. / ग्रा.यां. सेवा/ 2024 कोण्डागांव, दिनांक 28/11/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत डी एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल जोनल निविदा आमंत्रित की जाती है सभी कार्यों की जोनल निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 11.12.2024 शाम 5.00 बजे तक।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	2	3
	जोनल निविदा रू. 10.00 लाख से कम लागत के विभिन्न प्रकार के भवनों में विद्युतीकरण कार्य हेतु -	
1	विकासखण्ड कोण्डागांव	20.00
2	विकासखण्ड माकड़ी	20.00
3	विकासखण्ड फरसगांव	20.00
4	विकासखण्ड केशकाल	20.00
5	विकासखण्ड बड़ेराजपुर	20.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट http://res.cg.gov.in दिनांक 30.11.2024 से देखी एवं डाऊनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव

जी-242504216/3

पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे Credible Chhattisgarh विश्वसनीय छत्तीसगढ़

डोनाल्ड ट्रम्प की विजय और भारत

सुरेश हिंदुस्तानी

अमेरिका में रिपब्लिकल पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद अब यह तय हो गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका का इतिहास बताता है कि ट्रम्प की यह जीत उनकी ऐतिहासिक वापसी है। अमेरिका में यह विजय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 130 वर्ष के अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार है, ज़ब किसी ने यह कारनामा किया है।

वैश्विक राजनीति के जानकार डोनाल्ड ट्रम्प की जीत कई निहितार्थ निकाल रहे हैं। कई विश्लेषक ट्रम्प की जीत को भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर भी स्वीकार कर रहे हैं। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सरकार जिस नीति और विचार को लेकर कार्य कर रही है, उसकी झलक ट्रम्प के विचारों में भी दिखाई देती है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका की खोई ताकत को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आज अमेरिका कहने मात्र को ही महाशक्ति है, लेकिन उसका वैसा दबदबा आज नहीं है, जो पहले हुआ करता था। इस बीच भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से अपने कदम बढ़ाए हैं, इसलिए आज विश्व के अनेक देश भारत को महाशक्ति के रूप में देखने लगे हैं। हमें स्मरण होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के दौरान भारत के नागरिक पूरे सम्मान के साथ भारत लौटे थे। उस समय भारत के नागरिकों के समक्ष यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार नीचे कर लिए थे। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि भारत की शक्ति का ही परिचायक था। भारत की इस बढ़ती शक्ति से अमेरिका भी भली भांति परिचित है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कई बार यह कहा जा चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि आज का भारत विश्व के लिए एक ताकत बन चुका है। अमेरिका के इस चुनाव में भारत के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रचार किया गया। कई प्रकार के नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किए गए। वामपंथी विचार के मीडिया ने ट्रम्प की राह में अवरोध पैदा करने के भरसक प्रयास किए। यहां तक कि उनको सनकी और विलेन कहने में भी गुरेज नहीं किया गया। यही तो भारत में किया गया। वामपंथी समूह ने भारत के लोकसभा चुनावों में सरकार के विरोध में जहरीली भाषा का प्रयोग किया। फिर भी आख़िरकार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। अब ऐसा लगने लगा है कि मतदाता बहुत समझदार हो गया है। उसको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता। उसे अब देश दुनिया की समझ हो गई है, इसलिए वह वर्तमान के साथ कदम मिलाकर चलने की ओर अग्रसर हुआ है। विश्व के कई देश आज कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना के बाद कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उसे पटरी पर लाने के लिए उस देश की सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इन समस्याओं में कई समस्याएं ऐसी हैं, जो सबके सामने हैं। आतंकवाद एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। अमेरिका भी इससे ग्रसित है। अमेरिका में ट्रम्प की जीत से भारत के पड़ोसी देश यानि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में सुगबुगाहट प्रारम्भ हो गई है, क्योंकि यह देश भारत को हमेशा अस्थिर करने की फिराक में रहते हैं। हम वह वाकिया अभी तक भूले नहीं हैं, ज़ब अमेरिका ने आतंक के विरोध में बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था, हालांकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, लेकिन आतंक के विरोध में ट्रम्प का भी वैसा ही रवैया माना जा सकता है। इसी प्रकार चीन के समक्ष भी स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान से आतंक के विरोध में कार्यवाही करने के लिए कहता है, लेकिन जो देश आतंक के आकाओं के सहारे ही चल रहा हो, वह आतंक के विरोध में कैसे कार्यवाही कर सकता है। अब अमेरिका में ट्रम्प के पुन: आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अब पाकिस्तान दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आतंक के आकाओं के खिलाफ एक्शन लेगा।

राहुल को राजनीति के कुछ सबक सीखने होंगे

ललित गर्ग

कांग्रेस की उलटी गिनती का क्रम रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के नतीजे इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस न तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पा रही है और न ही देशहित के प्रभावी मुद्दे उठा पा रही है। देश में कॉर्पोरेट विरोधी जो एकसूत्री एजेंडा राहुल ने अपनाया है, या संविधान-रक्षा एवं धर्म-निरपेक्षता के नाम पर एक सम्प्रदाय-विशेष की जो राजनीति वह कर रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं, उनके इन मुद्दों के पक्ष में वोट नहीं मिले हैं। निश्चित ही राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई एक चीज है, जो नहीं बदली है, तो वह है भाजपा को मात देने में कांग्रेस की अक्षमता। भाजपा से सीधी टक्कर में कांग्रेस की हार का औसत प्रतिशत बढ़ता ही जा रहे हैं। अब तो कांग्रेस के मुद्दों से इंडिया गठबंधन के सहयोग दल ही कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। भाजपा जब कांग्रेस से मुकाबले में होती है तब उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। जबकि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले राहुल का जादू फीका पड़ता है। इसके उदाहरण हैं झारखंड के हेमंत सोरेन और बंगाल की ममता बनर्जी जिन्होंने उपचुनाव में सारी सीटें जीत ली। कांग्रेस के लिये जटिल से जटिलतर होते हालातों में केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हुई भारी जीत कांग्रेस पार्टी के लिये एक उत्साहजनक संदेश हो सकता है। निश्चित रूप से प्रियंका के राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी के लिये यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगा अक्षमता एवं अपरिपक्व राजनीति का दाग इससे कैसे कम हो सकता है?

राहुल गांधी संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर पूरी तरह हमलावर रहते हैं, वे गैर-जरूरी मुद्दों को लेकर अक्सर संसद की कार्रवाई को बाधित करते हैं। अडाणी एवं कॉर्पोरेट विरोधी उनका एजेंडा देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये कितना नुकसानदायी साबित होता रहा है, देश की जनता ने इसे महसूस किया है। राहुल दस साल से यह गलती कर रहे हैं और उनकी पार्टी इसकी कीमत चुका रही है। कांग्रेस और विशेष रूप से उसके नेता राहुल गांधी न जाने कब से अदाणी समूह को कोस रहे हैं। एक अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद वह हाथ धोकर इस समूह के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन शायद वह यह देखने से इन्कार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस के इस रवैये से सहमत नहीं है। विभिन्न राज्यों में जहां-जहां इंडिया गठबंधन दलों की सरकारें हैं, वे ऐसे मुद्दों से दूरी बनाना चाहते हैं।

ममता बनर्जी ने जिस तरह यह कहा कि उनका दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी एक मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगा, उससे यही संकेत मिला कि वह नहीं चाहतीं कि अदाणी मामले को तूल दिया जाए। कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि गत दिवस ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने बंदरगाह के विकास के लिए अदाणी समूह के साथ एक पूरक समझौते को अंतिम रूप दिया। साफ है कि माकपा भी अदाणी मामले में कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं। तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह के साथ एक समझौता कर रखा है और अतीत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में इस समूह के निवेश को हरी झंडी दी थी। आखिर राहुल गांधी इन स्थितियों को क्यों नहीं समझ एवं देख रहे हैं? यदि राहुल गांधी को यह लगता है कि अदाणी समूह दागदार है तो वह अपनी सरकारों को उससे कोई नाता न रखने के लिए क्यों नहीं कह पा रहे हैं? यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस अमेरिकी अदालत के आकलन को अंतिम सत्य की तरह क्यों ले रही है और वह भी तब, जब उसने रिश्वत के कथित लेन-देन के कोई प्रमाण नहीं पेश किए हैं?

नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी अपनी इस आक्रामकता से हासिल क्या करना चाहते हैं। विडम्बना देखिये कि संयुक्त अरब अमीरात, तंजानिया और श्रीलंका जैसे देश अदाणी समूह पर अमेरिकी अदालत की टिप्पणी को महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस के नेता और कुछ अन्य लोग उसे बिनी किसी जांच-पड़ताल दंडित करने को उतावले हैं। यह उतावलापन इसलिए भी ठीक नहीं, क्योंकि निवेशक अदाणी समूह पर भरोसा जता रहे हैं और इसी कारण उसके शेयरों में तथाकथित अमेरीकी कार्रवाई से भारी गिरावट के बाद पुन: तेजी देखने को मिल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जिस तरह की बातें कह एवं कर रहे हैं, निश्चित ही यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रहा है, वे लगातार विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहन देते हुए भूल जाते हैं कि उनके ऊपर देश को तोड़ने नहीं, जोड़ने की जिम्मेदारी है। प्रश्न है कि कब राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए उसके साथ न्याय करेंगे? वे जानते नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उससे क्या नफा-नुकसान हो रहा है या हो सकता है।

हर जगह कांग्रेस अपने मजबूत सहयोगियों के बूते सीटें जीतने में कामयाब रही है। ओडिशा में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। एक वक्त में पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब वहां भाजपा छाई हुई है। जबकि इन राज्यों की डेमोग्राफी कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन सरकारें भाजपा की है। कांग्रेस मुद्दे नहीं तय कर पा रही है। बीजेपी हर राज्य के हिसाब से मुद्दे तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट के हिसाब के मुद्दों के हिसाब से बोलते हैं। वहां के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक परिस्थितियां सबको ध्यान में रख कर बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस इसके हिसाब से मुद्दे और रणनीति तय नहीं कर पाती। बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। आखिर उसकी रणनीति में कहां खामी है और वो बार-बार कहां चूक रही है?

लगभग जीत के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ यही किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र में भी दोहराया गया। झारखंड में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई वाले गठबंधन में शामिल थी और वो 2019 में जीती 16 सीटों में एक भी सीट का इजाफा नहीं कर पाई। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह नाकाम रही। कांग्रेस 90 में से छह सीटें ही जीत पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बन कर किसी तरह अपनी नाक बचा पाई। भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा। इसी के हिसाब से नारे गढ़े। लाडकी बहिन जैसी लाभार्थी योजना, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाई। लेकिन राहुल गांधी ऐसे चुनावी मुद्दों को गढ़ने में क्यों असफल रहे? आखिर कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी इन स्थितियों पर गंभीर मंथन क्यों नहीं करते?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का राग अलापते हुए देश में मुस्लिमों का तो पक्ष लेते हैं लेकिन बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में हिन्दुओं पर हो अत्याचारों पर मौन साध लेते हैं। उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति पर अड़े हैं। राहुल गांधी बेतुकी आक्रामकता से उपरत क्यों नहीं हो रहे हैं? वे सदन के भीतर एवं सदन के बाहर ऐसी ही तर्कहीन बातों एवं बयानों से अराजक माहौल बना रहे हैं। आखिर वह जो कुछ मोदी सरकार से चाह रहे हैं, उसे कांग्रेस संगठन और साथ ही अपने दल द्वारा शासित राज्य सरकारों में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है? लोकसभा की कार्रवाई कांग्रेसी एवं विपक्षी सांसदों के वाक आउट, हंगामे, अनर्गल बहस की भेंट चढ़ रही है। विपक्षी दल अपनी सार्थक भूमिका का निवर्हन करने की बजाय लगातार सत्तापक्ष को घेरने एवं आरोप-प्रत्यारोप की घटिया राजनीति में लगा है। देश भी इन त्रासद घटनाओं से कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

गरुड़पुराण- तार्थ्यो वै पश्यतो राजेत्याह तस्य बचासि विश: (शतपथ 13।4।3।13)

अर्थात् - पक्षियों का राजा गरड है और पक्षी ही उसकी प्रजा हैं, वह पुराण का ज्ञाता है। पुराणं वेद।

कूर्मपुराण- स यत्कूर्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापति: प्रजा असृज । (शतपथ 10।5।1।5)

अर्थात् - जो कूर्म नामक पुराण है वह कूर्मरूपी परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि का प्रतिपादक है ।

मत्स्यपुराण- तस्य (मनो:) अवनेनिजातस्य मत्स्य: पाणौ आपेदे । (शतपथ 1।8।1।1-2)

अर्थात् - मनुजी के अवनेजन करते हुए एक मत्स्य अंजलि में आ गया (इसी मत्स्यावतार का कथन किया हुआ मत्स्यपुराण है ।)

वाराहपुराण- वराहेण पृथिवी संविदाना । (अथर्व 12 । 1।48)

अर्थात् - वाराह ने पृथिवी को प्रबुद्ध किया (उक्त संवाद को ही वाराहपुराण कहते हैं ।)

वामनपुराण- इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढमस्य पासुरै । (ऋग्वेद 1 । 22 । 17)

अर्थात् - वामनावतारधारी विष्णु ने इस ब्रह्माण्ड को तीन चरणों में झाक्रान्त कर पद भरे हैं। और यह सब लोक उसके धूलि-धूसर पांव में अन्तर्हित हो गया (इसी चरित्र का विस्तार %बामनपुराण% में किया गया है।)

ब्रह्माण्डपुराण- य आण्डकोशे भुवनं विर्भात । (तैत्तिरीय 3 । 12)

अर्थात् - जो प्रजापति ब्रह्माण्ड में स्थित होकर भुवन की रक्षा करता है, (उसी की महिमा का बोतक ब्रह्माण्डपुराण है।)

इसी प्रकार अन्यान्य पुराणों के भी साक्षात् नामों को या तत्तत्रति- पादित विशेष वृतान्तों को वेदों में से निकाला जा सकता है।

क्रमश: ...

'विश्व एड्स दिवस'

योगेश कुमार गोयल

'एड्स' न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में लोगों के लिए आज भी एक भयावह शब्द है, जिसे सुनते ही भय के मारे पसीना छूटने लगता है। एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम) का अर्थ है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने से अप्राकृतिक रोगों के अनेक लक्षण प्रकट होना। एच.आई.वी. संक्रमण के बाद एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की मामूली से मामूली बीमारियों का इलाज भी दूभर हो जाता है और रोगी मृत्यु की ओर खिंचा चला जाता है। आज भी यह खतरनाक बीमारी दुनियाभर के करोड़ों लोगों के शरीर में पल रही है। एड्स महामारी के कारण अफ्रीका के तो कई गांव के गांव नष्ट हो चुके हैं। 'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में एड्स महामारी शुरू होने के बाद से 77 मिलियन से भी अधिक लोगों में इसका वायरस फैल चुका है। वर्ष 2017 में विश्वभर में करीब 40 मिलियन लोग एचआईवी संक्रमित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2022 के अंत तक 3.9 करोड़ से भी ज्यादा लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे। एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एक विशेष थीम के साथ 'विश्व एड्स दिवस' मनाया जाता है।

वैसे एड्स का इतिहास काफी दिलचस्प है। दरअसल 1981 में न्यूयार्क तथा कैलिफोर्निया में न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, कपोसी सार्कोमा तथा चमड़ी रोग जैसी असाधारण बीमारी का इलाज करा रहे पांच समलैंगिक युवकों में एड्स के लक्षण पहली बार मिले थे। चूंकि जिन मरीजों में एड्स के लक्षण देखे गए थे, वे सभी समलैंगिक थे, इसलिए उस समय इस बीमारी को समलैंगिकों की ही कोई गंभीर बीमारी मानकर इसे 'गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी' (ग्रिड) नाम दिया गया था। इन मरीजों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता असाधारण रूप से कम होती जा रही थी लेकिन कुछ समय पश्चात् जब दक्षिण अफ्रीका की कुछ महिलाओं और बच्चों में भी इस बीमारी के लक्षण देखे जाने लगे, तब जाकर यह धारणा समाप्त हुई कि यह बीमारी समलैंगिकों की ही बीमारी है। तब गहन अध्ययन के बाद पता चला कि यह बीमारी एक सूक्ष्म विषाणु के जरिये होती है, जो रक्त एवं यौन संबंधों के जरिये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। तत्पश्चात् इस बीमारी को एड्स नाम दिया गया, जो एचआईवी नामक वायरस द्वारा फैलती है।

यह वायरस मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है और धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यही स्थिति 'एड्स' कहलाती है। अगर एड्स के कारणों पर नजर डालें तो मानव शरीर में एचआईवी का वायरस फैलने का मुख्य कारण हालांकि असुरक्षित सेक्स तथा अधिक पार्टनरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही है लेकिन कई बार कुछ अन्य कारण भी एचआईवी संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

भाजपा ने साबित किया डर के आगे जीत है?

अमिताभ श्रीवास्तव

लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार चार सौ पार' के नारे से झटका खा चुकी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया है कि वह आम चुनाव में अति आत्मविश्वास की शिकार थी। उसने महाराष्ट्र में 45 सीटों को जीतने का सपना इतनी आसानी से देखा कि उसे जमीनी स्तर पर जीत का सहजता से ही बोध होने लगा था। किंतु ताजा राज्य के चुनाव में किसी भी प्रकार की गलती न करते हुए उसने लगभग नब्बे प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार उसने लोकसभा चुनाव के विपरीत आरंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) की आवश्यकता को माना।

उसने केवल विकास के नारे से विजय तक नहीं पहुंच पाने की बात मानी। हिंदुत्व के नारे को अपनी असलियत और जरूरत मान कर अपने मतदाताओं को जगाने की कोशिश की, जिसने छप्पर फाड़ सफलता के साथ एक नया इतिहास रच दिया। यहां तक कि राज्य के सत्ताधारी महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट तथा शिवसेना शिंदे गुट को भी इतना सहारा दिया कि वे भी उम्मीद से कहीं आगे निकल आए। इसके साथ ही पिछले चुनाव परिणामों की दृष्टि से राज्य में पहली बार किसी गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत दर्ज हुआ।

आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे नौ सीटों पर सफलता मिली थी। कुछ सीटों पर उसकी कांटे की टक्कर हुई थी। मतों के हिसाब से उसे कुल 26.18 प्रतिशत मिले थे। यह आंकड़ा वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले 27.83 प्रतिशत मतों से बहुत कम नहीं था।

सिर्फ सीटों के लिहाज से 23 का आंकड़ा सीधे नौ पर जा पहुंचा था। वहीं शिवसेना का शिंदे गुट भी 12.96 प्रतिशत मत लेने में सफल रहा था, जिनसे उसे सात लोकसभा सीटें मिली थीं। साथ ही यह संख्या शिवसेना के ठाकरे गुट से बहुत कम नहीं थी। यहां तक कि शिवसेना के ठाकरे गुट के 16.72 प्रतिशत मत शिंदे गुट से बहुत ज्यादा नहीं थे।

हालांकि गठबंधन के लिहाज से सबसे अधिक नुकसान में राकांपा अजित गुट ही रहा था, जिसे एक सीट और 3.6 प्रतिशत मत ही मिले थे। इस स्थिति पर विचार के बाद महागठबंधन ने अपनी गलतियों के कारण ढूंढ़ने आरंभ किए। सुधार की श्रृंखला में सबसे पहले 'लाड़ली बहन' योजना आरंभ हुई। फिर 'लाड़ला भाऊ' से लेकर किसानों को हर तरह की राहत दी गई।

इसके बाद अलग-अलग समाजों को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में महामंडलों का गठन कर डाला। चुनाव और आचार संहिता की मर्यादा को देखते हुए 'लाड़ली बहन' योजना की अग्रिम राशि महिलाओं के खाते तक पहुंचा दी, जो दीपावली त्यौहार पर आकर्षण का केंद्र बनी। जब सबकुछ देना हो गया तो शुरू हुआ प्रचार, जो दो भाग में हुआ।

जिसका पहला भाग था चुनाव की घोषणा के पहले और दूसरा भाग था चुनाव की घोषणा के बाद, जिसमें रणनीति की आक्रामकता का अंतर साफ दिखा। साधु-संत से लेकर आरएसएस तक सभी अपने मोर्चों पर डटे दिखे। भाजपा को यह मालूम था कि आम चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में रक्षात्मक खेलने से बड़ा नुकसान हो सकता है।

इसलिए उसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदर्भ क्षेत्र के लिए सहारा लिया, जो अपना नारा अपने प्रदेश से बुलंद कर चुके थे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी क्षेत्र से प्रचार आरंभ करने के लिए पहुंचे। दोनों के नारों में कहीं न कहीं हिंदू समाज के एकजुट होने की ध्वनि थी। योगी आदित्यनाथ का नारा सभाओं में चला, तो प्रधानमंत्री मोदी का नारा विज्ञापनों का सहारा बना।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस तो दोनों के नारे ले उड़े और उन्होंने अपनी हर सभा में दोनों नारों का प्रयोग किया। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रत्यक्ष विरोध किया। उन्होंने एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ विकास का तीखा बखान किया। स्पष्ट था कि उनके तीखेपन को प्रतिक्रिया मिलेगी और चुनाव की दिशा बदलेगी, जिसकी चपेट में सबसे पहले ओवैसी बंधु आए,

जो नारों का जवाब देने की बजाय उन पर सवाल-जवाब करते आए। उन्होंने रक्षात्मक रणनीति अपनाई, जिससे भाजपा को अधिक आक्रामक होने का अवसर मिला। उधर, कांग्रेस ने अपनी शुरुआत बीते लोकसभा चुनाव की परिपाटी के आधार पर की और संविधान, किसान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान काफी सुना जा चुका था,

लेकिन वे भाजपा को पूरी तरह सत्ता से बाहर करने में विफल रहे थे। इस बार चुनाव क्षेत्र का स्तर अलग होने से मतदाताओं के समक्ष अपील भी अलग अपेक्षित थी। मगर पुरानी फिल्म ही चली। हालांकि कांग्रेस ने माहौल को देखकर स्पष्ट किया था कि वह आक्रामक नहीं होगी और अपने स्तर को बनाए रखेगी। इस बात को भाजपा ने कांग्रेस की कमजोरी बनाया और आक्रमण कम या कमजोर नहीं होने दिया।

भाजपा ने पहले अपनी योजनाओं में महिला-पुरुष को अलग-अलग किया, फिर धर्म और अंत में जाति के नाम पर सीधी-सीधी रेखाएं खींचीं, जिनसे निचले स्तर के मतदाता को स्पष्ट संदेश गया और उनमें छिपा डर लोगों के मन में कहीं न कहीं जगह बनाने में सफल हुआ। भाजपा को मालूम था कि बस इसी के आगे उसकी जीत है, जिसे धमाकेदार अंदाज में दर्ज कर दिखाया गया।

चुनाव में अधिक दल होने और बगावत होने के कारण नतीजे कम अंतर से आने की संभावना थी, इसलिए अधिक मतदान का प्रयास किया गया। यही आधार मामूली अंतर के फैसलों में काम आया और लोकसभा चुनाव में 26.18 प्रतिशत मत पाने वाली भाजपा पांच महीने बाद 149 सीटों पर 26.77 प्रतिशत मत पाकर 132 सीटें जीतने में सफल हो गई। आम तौर पर एक लोकसभा सीट का गठन छह विधानसभा सीटों को मिलाकर होता है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक मोटे आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा को करीब 22 लोकसभा सीटों के बराबर बहुमत मिला, जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की सफलता के लगभग बराबर है। बस उसने इन परिणामों से मतों के लिए थोड़ा उन्मादी बनना सीख लिया है। आक्रामक हिंदुत्व की कड़वी गोली को विकास की मीठी परत के साथ खिलाने से अपनी समस्या का हल जान लिया है। संभव है कि अब यह अंदाज भाजपा की चुनावी शैली का भाग बने, क्योंकि यह बात पक्की हो चुकी है कि डर के आगे जीत है।

आज का इतिहास

1878 व्हाईट हाउस में पहला टेलीफोन स्थापित किया गया।
1910 पर्फरियो डाएज को मेक्सिको का आठवां राष्ट्रपति बनने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया।
1913 फोर्ड मोटर कंपनी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पहली बार मूविंग असेंबली लाइन तकनीक पेश की।
1913 फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया की पहली चलती विधानसभा लाइन का संचालन शुरू किया।
1918 संघ के अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के साथ, डेनमार्क ने डेनमार्क के साम्राज्य को एक आम सम्राट के माध्यम से व्यक्तिगत संघ में एक पूर्ण संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी।
1932 उत्तरी मॉन्ट्रियल शहर में 6 वर्ग मील के दायरे में सीवरों और गैस पाइपों में विस्फोट से अभ्यर्थियों में दहशत और डर पैदा हो गया।
1941 युनाइटेड एयर फ़ोर्स के नागरिक सहायक, सिविल एयर पेट्रोल की स्थापना की गई थी।
1948 ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहन रहस्यों में से एक में, एक अज्ञात व्यक्ति का शव एडिलेड के सोमरटन समुद्र तट पर पाया गया, जो आज एक मामला है।
1952 एडॉल्फो रूइज़ कॉरटिन ने मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला।
1955 अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, मॉन्टगोमरी बसबायकोट को उगलते हुए, मॉन्टगोमरी, अलबामा में एक सार्वजनिक बस्टो पर एक सफेद आदमी को अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने के लिए रोजा पार्क्स को गिरफ्तार किया गया था।
1958 शिकागो में हमारी लेडी ऑफ एंजल्स स्कूल ग्रेड स्कूल में आग लगने से 90 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल में बिना छिड़काव के आग लगने की स्थिति में ठीक से तैयार नहीं किया गया था और कोई आग नहीं लगी थी।
1959 संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों की विधानसभाओं द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संधि के अनुसार, अंटार्कटिका को एक वैज्ञानिक रिजर्व के रूप में स्वीकार किया गया है जो किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि से मुक्त होगा।
1959 बारह देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, शीत युद्ध के दौरान स्थापित पहला हथियार-संचालन समझौता, अंटार्कटिक में सैन्य गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने और महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में स्थापित करने के लिए।
1970 लुइस एकेवेरिया मेक्सिको के राष्ट्रपति बने।

मणिपुर में हिंसा और पूर्वोत्तर की राजनीति

आदिति फडणीस

नैशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राज्य की 60 सदस्यीय विधान सभा में भाजपा के 32 विधायक हैं। सात विधायकों वाली एनपीपी के पीछे हटने से पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।

विशेष बात यह है कि एनपीपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तर्ज पर बनाए गए राजनीतिक मोर्चे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस से अलग नहीं हुई है। पार्टी उन गठबंधन सरकारों में भी बनी साझेदार है, जिनमें भाजपा शामिल है।

मेघालय में 31 विधायकों वाली एनपीपी सरकार को भाजपा के दो विधान सभा सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है। नागालैंड में एनपीपी के 5 एमएलए हैं और वह नैशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में पांच सदस्यों वाली एनपीपी भाजपा नीत सरकार में हाथ बंटा रही है।

मणिपुर में एनपीपी अध्यक्ष कॉनराड संगमा की मांग है कि भाजपा एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए तो वह सरकार को दोबारा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भले ही संगमा सरकार से हटने को अपने दिल की आवाज पर उठाया गया कदम बता रहे हों, लेकिन इसमें भी राजनीति और स्वार्थ झलकता है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हिंसा की हाल की घटनाओं में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। मणिपुर में लगभग 50 फीसदी आबादी मैतेई समुदाय की है।

मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने की बात कही थी। इसी आधार पर जब मैतेई लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाई तो राज्य के अन्य जनजातीय समूहों के साथ 2023 में व्यापक स्तर पर हिंसा भड़क उठी।

मैतेई समुदाय को आरक्षण की व्यवस्था किए जाने का मतलब होगा कि राज्य के कुकी-जो और नागा जैसे दो प्रमुख जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण में से उसे भी हिस्सा दिया जाएगा। बस, इसी को लेकर पूरे पूर्वोत्तर में स्थिति बिगड़ गई। मैतेई समुदाय के लोग असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में रहते हैं, लेकिन मणिपुर में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है।

कुकी-जो समुदाय के लोग भी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैले हैं। इस जनजाति की जड़ें चूंकि म्यांमार की चिन जनजाति से मिलती हैं, इसलिए इस पड़ोसी देश में जब से तख्तापलट हुआ है तब से बड़ी संख्या में शरणार्थी वहां से भारत आ रहे हैं। इससे मैतेई समुदाय में यह भय घर कर गया है कि यदि इसी तरह शरणार्थी आते रहे तो कुकी-जो की संख्या राज्य में उनसे ज्यादा हो जाएगी।

मणिपुर में होने वाली घटनाओं पर असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने संज्ञान लिया है। सभी चाहते हैं कि हिंसा रुकनी चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर

मतभेद हैं कि यह काम किस प्रकार अंजाम दिया जाए। हथियारों से लैस उग्रवादी समूह क्षेत्र में सभी सरकारों के लिए संकट का सबब बने हुए हैं। लेकिन, संगमा के समक्ष दोहरी चुनौती है। हिंसा की बढ़ती घटनाओं के विरोध में अपनी पार्टी और स्वयं के हितों के लिए कुछ भी निर्णय लेते समय उन्हें अपने वोट बैंक को ध्यान में रखना होगा।

मणिपुर सरकार में साझेदार होने के बावजूद संगमा के विधायक सभी प्रकार के लाभ से वंचित हैं। उनमें से अधिकांश ने राज्य की भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही है। लेकिन, वर्ष 2007 से 2012 तक मणिपुर के पुलिस महानिदेशक, एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली पहली सरकार में मंत्री रहे और अब एनपीपी के उपाध्यक्ष वाई जॉय कुमार जैसे नेताओं का मानना है कि भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने से उनकी पार्टी गर्त में चली जाएगी।

गारो जनजाति से ताल्लुक रखने वाले संगमा अच्छी तरह जानते हैं कि मणिपुर में असुरक्षित महसूस कर रहे कुकी-जो जनजाति के लोगों को मेघालय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह यह भी जानते हैं कि यदि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी एनपीपी का विस्तार करना है तो सहानुभूति के साथ इस जनजाति को साथ लेकर चलना ही होगा।

इसीलिए संगमा सरकार ने अपने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कुकी-जो समुदाय के उन लोगों की मदद करें, जो मणिपुर से भाग कर मेघालय आ गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली से भी यह इच्छा जाहिर की थी कि वह विभिन्न समूहों के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थता करना चाहते हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से उनकी समस्याओं को समझ कर पूरी तरह दूर किया जा सके। इसमें एक-एक शब्द बड़ी ही सावधानी से चुना गया था, ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। लेकिन, उनकी इस अपील का कोई असर नहीं हुआ।

उल्टे मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उनकी पार्टी के सदस्यों को सरकार में किसी भी प्रकार की सलाह-मशविरे की प्रक्रिया से दूर कर दिया और हिंसा की छिटपुट घटनाओं को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया। धीरे-धीरे कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र में अपना चुनावी अभियान छोड़कर मणिपुर जाना पड़ा।

पूर्वोत्तर की राजनीति में कॉनराड संगमा कोई अनजान चेहरा नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि उत्तर-पूर्व के राज्यों की राजनीति उनकी रग-रग में समाई है। उनके पिता पीए संगमा वर्षों तक कांग्रेस में हैसियत वाले नेता रहे। कॉनराड को भी युवा और महत्त्वाकांक्षी राजनेता माना जाता है जो पूर्वोत्तर के राजनीतिक पटल पर नाम कमाना चाहते हैं। वह स्थानीयता पहचान और धर्म के लिए भी काफी मुखर होकर आवाज उठाते हैं। उन्होंने यूनिफार्म सिविल कोड का भी खुलकर विरोध किया और तर्क दिया कि यह गलत है, क्योंकि यह मेघालय की संस्कृति से मेल नहीं खाता है।

उन्होंने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का भी विरोध किया और मांग की कि मेघालय एवं असम को सीएए से अलग रखा जाए। मालूम हो कि मेघालय में ईसाई समुदाय की जनसंख्या अधिक है। यह जानते हुए कि मणिपुर सरकार को उनका समर्थन व्यापक तौर पर अप्रांसगिक ही है और सरकार से हटने पर उनके विधायक भाजपा के पाले में भी जा सकते हैं, जिससे उन्हें भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके बावजूद संगमा ने अपने मौजूदा कदम से एक बड़ा दांव खेला है। कुकी-जो समुदाय की नजर में उनकी अहमियत काफी बढ़ गई है। उनका रुख कितना कारगर साबित होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा।

बांग्लादेश आखिर किस भविष्य की ओर बढ़ रहा है?, हालात बद से बदतर

शोभना जैन

राजनीतिक अस्थिरता में फंसे बांग्लादेश में हालात दिनोंदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी अस्थिरता की स्थिति में धार्मिक कट्टरता हावी होती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के उत्पीड़न, उनके धार्मिक स्थलों, व्यापारिक ठिकानों, घरों पर दिनोंदिन हमले, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जेल भेजने के बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारत के अनेक राजनेताओं, धर्मगुरुओं ने इन घटनाओं की तीव्र आलोचना करते हुए चिन्मय दास की अविलंब रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कुछ लोगों ने इस्कॉन पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इस संबंध में एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से अतिवादियों को यह कह कर संरक्षण दे दिया कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। जबकि स्वयं उन्हीं के देश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने यूनुस के इस बयान पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यूनुस हिंदुओं पर हिंसा की घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए स्थिति की गंभीरता को कम आंकने के प्रयासों में जुटे हैं। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ कर जा चुकी हैं। फिलहाल देश में यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि इस सबके बीच एक नाटकीय घटनाक्रम में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तथा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। खालिदा को इस अपराध में सात साल की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश जबकि घोर अस्थिरता और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में खालिदा की रिहाई के आखिर क्या मायने हैं, राजनैतिक पटल पर उनकी भूमिका क्या हो सकती है? भारत के अनेक प्रतिपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश के एक जानकार के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से यहां कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा जहां अल्पसंख्यक अपने आपको इतना असुरक्षित महसूस करते हों। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की आबादी में लगभग आठ प्रतिशत की हिस्सेदारी हिंदुओं की है। भारत ने बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश न केवल भारत का महत्वपूर्ण भू-राजनैतिक सहयोगी है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अहम है। उसकी भूमि तीन ओर से भारत की सीमाओं से घिरी है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। सबसे अहम है कि दोनों देशों की जनता गहरे भावनात्मक रिश्तों से जुड़ी है, दोनों के गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते हैं। कई बार दोनों देशों के संबंधों में उतार-चढ़ाव भी आए लेकिन यहां कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा कि अल्पसंख्यक अपने आपको इतना असुरक्षित महसूस करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि बांग्लादेश में जल्द राजनीतिक अस्थिरता समाप्त होगी जिससे सामाजिक समरसता का माहौल बहाल हो सकेगा। शांतिपूर्ण स्थिर बांग्लादेश न केवल भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा है, बल्कि वह इस क्षेत्र के लिए भी बेहतर है।

नए सीएम के फैसले का पालन करेंगे एकनाथ शिंदे?

राहिल नोरा चोपड़ा

शिवसेना चाहती थी कि एकनाथ शिंदे को फिर से सी.एम. बनाया जाए या उन्हें अढ़ाई साल का कार्यकाल दिया जाए। हालांकि, भाजपा ने इसे खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि वह नए सी.एम. के उनके फैसले का पालन करेंगे। जबकि शिवसेना ने संकेत दिया कि वह नई व्यवस्था में डिप्टी के तौर पर काम नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा मुख्यमंत्री पद की भरपाई के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 3 बड़े विभागों सहित महाराष्ट्र के 12 कैबिनेट पद दे सकती है। महायुति गठबंधन में तीसरी पार्टी अजित पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी. को वित्त विभाग सहित कैबिनेट में 9 सीटें मिल सकती हैं।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं और भाजपा द्वारा आधे पद अपने पास रखने की संभावना है। जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडऩवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। नेताओं ने मुख्यमंत्री पद, कैबिनेट में जगह और शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के सी.एम. के लिए फडऩवीस के नाम को मंजूरी दे दी गई। टी.एम.सी. का नजरिया भी अलग ्कांग्रेस के दृष्टिकोण के विपरीत, जो लगातार उद्योगपति गौतम अडानी के समूह पर संयुक्त राज्य अमरीका में धोखाधड़ी

और रिश्वतखोरी के आरोपों का मुद्दा उठा रही है, टी.एम.सी ने कहा है कि वह लोगों से जुड़े मुद्दों पर अपना जोर जारी रखेगी। टी.एम.सी. नेतृत्व ने उन मुद्दों की पहचान की है, जिन पर वह संसद के दोनों सदनों में चर्चा करना चाहती है।

ये मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति और पश्चिम बंगाल को कथित तौर पर केंद्रीय धन से वंचित करना। टी.एम.सी. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के 'इंडिया' ब्लॉक का घटक होने के बावजूद चुनावी तौर पर समूह के साथ सांझेदारी नहीं करती है। इसने कहा है कि भले ही वह ब्लॉक का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन उसका नजरिया भी अलग है।

राजस्थान में कांग्रेस की जीत एक बड़ा सबक और झटका: राजस्थान में 7 विधानसभा उप-चुनावों में से सिर्फ एक में कांग्रेस की जीत एक बड़ा सबक और झटका है, जिसका दोष पार्टी के 'इंडिया' ब्लॉक के तहत संयुक्त उम्मीदवार उतारने की बजाय अकेले चुनाव लडऩे के फैसले पर लगाया जा रहा है। उप-चुनाव में कांग्रेस ने दौसा सीट तो बरकरार रखी, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में जीती गई 3 अन्य सीटें उसके हाथ से निकल गईं।

इससे 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की ताकत घटकर 66 रह गई है। इस खराब प्रदर्शन का ठीकरा मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर फूटेगा। अब डोटासरा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, यह तय नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी आगामी फेरबदल में सचिन पायलट को राजस्थान का पी.सी.सी. प्रमुख नियुक्त कर सकती है।

झारखंड में डबल इंजन की कहानी पर लगी ब्रेक : डबल इंजन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के जोरदार प्रयास के बावजूद, पार्टी झारखंड के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल रही। हालांकि, पार्टी के पास 3 आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन हैं। भाजपा के चुनाव अभियान का नेतृत्व असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कुशलतापूर्वक किया।

दूसरी ओर, 'इंडिया' ब्लॉक के 2 प्रमुख चेहरे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। कल्पना सोरेन इस चुनाव में प्रमुख नेता के रूप में उभरीं। हेमंत सोरेन ने खुद को गठबंधन के नेता के रूप में प्रभावी रूप से स्थापित किया। संथाल परगना क्षेत्र में बंगलादेशी घुसपैठ की भाजपा की बयानबाजी असफल रही और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में विफल रही, जिसके कारण भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.)ने राज्य भर में 28 एस.टी.-आरक्षित सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बीच, राज्य में भाजपा की करारी हार के बाद राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत चुनाव प्रभारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हार के कारण भाजपा के भीतर महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलावों की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के नेतृत्व में नई जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है।

ओडिशा में कांग्रेस द्वारा नेतृत्व और संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा शुरू : 2024 के चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) द्वारा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओ.पी.सी.सी.) को भंग करने के 4 महीने बाद, कांग्रेस ने राज्य इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए नेतृत्व और संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा शुरू कर दी है। कांग्रेस राज्य में पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए एक नए चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वरिष्ठ नेता, जिनमें से कइयों को वर्षों से कई नेतृत्व भूमिकाएं दी गई हैं, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करने में असमर्थ रहे हैं। कांग्रेस में काफी चर्चा है कि मीनाक्षी नटराजन को ए.आई.सी.सी. महासचिव के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और उन्हें ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना और कोरापुट के सांसद सप्तगिरि उलाका के नाम सबसे आगे चल रहे हैं।

झारखंड में हेमंत सरकार की जीत के मायने

अनुज कुमार सिन्हा

झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों (कांग्रेस, राजद और भाकपा-माले) ने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन को 81 में से 56 सीटों पर (यानी 61.1 प्रतिशत सीट) जीत मिली है। एनडीए सिर्फ 24 सीट पर जीत दर्ज कर सका। अकेले झामुमो ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा 21 सीटों पर सिमट गयी। झारखंड बनने के बाद झामुमो का विधानसभा चुनाव में यह सबसे अच्छा और भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन है। लगातार दो चुनाव से झामुमो सबसे बड़ा दल बन कर उभरा है।

इस चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट में एक पर भी जीत नहीं मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को 28 आरक्षित (एसटी) सीटों में सिर्फ दो सीट (खूंटी-तोरपा) पर जीत मिली थी। ये दोनों चुनाव के नतीजे संकेत दे चुके थे कि झारखंड के आदिवासी भाजपा के साथ नहीं हैं। भाजपा जानती थी कि बगैर आदिवासियों को अपने साथ लिए झारखंड की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए उसने आरक्षित सीटों पर पूरी ताकत लगा दी। उसने झारखंड के अपने तमाम दिग्गज आदिवासी नेताओं को चुनाव में उतार दिया। उन्हें भी, जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे।

कोल्हान और संताल परगना झामुमो का गढ़ है। कोल्हान में 2019 के चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए भाजपा ने झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन और लोबिन हेंब्रम को पार्टी में शामिल कर लिया। इस उम्मीद में कि चंपाई सोरेन कोल्हान और लोबिन हेंब्रम संथाल परगना में झामुमो को रोकने में मदद कर पायेंगे। ये दोनों आदिवासी वोट को भाजपा के पक्ष में करने में असफल रहे। चंपाई सोरेन सिर्फ अपनी सीट बचा पाये। 28 आरक्षित सीटों में से सिर्फ एक सीट सरायकेला भाजपा के पक्ष में गयी। इससे यह साबित हो गया कि आरक्षित सीटों पर भाजपा की पकड़ नहीं है और झामुमो से नेता आयात कर वह आदिवासी सीट नहीं जीत सकती।

झामुमो का इतिहास रहा है कि उसके नेता दूसरे दलों में जब जाते हैं, तो उनके साथ झामुमो का आदिवासी वोट नहीं जाता। वहां तीर-धनुष पर वोट पड़ता है, न कि व्यक्ति के नाम पर। इंडिया गठबंधन जीता, क्योंकि उसके वोट बैंक (आदिवासी, मुसलिम और ईसाई) का आधार जरा-सा भी नहीं हिला, झामुमो, कांग्रेस और राजद सभी अपने-अपने समर्थकों का वोट गठबंधन के प्रत्याशी को शिफ्ट कराने में सफल रहे, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों के बीच यह बात बैठ गयी थी कि एक आदिवासी नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है।

जेल से रिहा होने के बाद जिस तरीके से शिबू सोरेन की तर्ज पर (लुक में भी) हेमंत सोरेन और कल्पना सारेन पूरे झारखंड में घूमे और अपनी बात रखी, उसका गहरा असर पड़ा। इस जीत का श्रेय कल्पना सोरेन के तूफानी चुनावी दौरे को भी जाता है। उनकी चुनावी सभाओं में उमड़ी भीड़ जनता से उनके बेहतर कनेक्ट को दर्शाती है। इस चुनाव में एक बड़ा फर्क दिखा सही समय पर सही निर्णय लेने का। मंईयां सम्मान योजना और बिजली बिल माफ करना तुरूप का पत्ता साबित हुआ। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कल्याणकारी योजनाओं को फोकस किया।

लड़कियों और महिलाओं के लिए मंईयां योजना आरंभ कर उनके खाते में राखी के दिन से एक-एक हजार रुपये डालना आरंभ किया। चुनाव होते-होते एक-एक बहन के खाते में चार हजार जमा हो चुके थे। भाजपा इस योजना की ताकत को देख रही थी और उसने काट में गोगो दीदी योजना की घोषणा की, 2,100 रुपये देने का वादा किया। हेमंत सोरेन ने भाजपा को समय नहीं दिया और दूसरे दिन ही 2,500 रुपये दिसंबर से देने का न सिर्फ वादा किया, बल्कि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे पहले विशेष कैबिनेट कर इस निर्णय को पास भी करवा दिया। इससे महिलाओं और लड़कियों में भरोसा बढ़ा।

बिजली बिल, कृषि ऋण माफ करने का असर दिखा। चुनाव के दो-तीन महीने पहले से सरकार ने आंदोलन कर रहे, मानदेय-वेतन बढ़ाने, स्थायी करने, ओल्ड पेंशन स्कीम देने की मांग करनेवालों की बातें सुनी और उनकी मांगें मानते गये। इससे सरकार के प्रति नाराजगी नहीं रही। हेमंत सरकार यह बताने में सफल रही कि गरीबों की सरकार है और केंद्र बकाया दे, तो हर परिवार को अधिक से अधिक राशि दी जायेगी।

इसके ठीक विपरीत भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जिसका असर ही नहीं पड़ा, भ्रष्टाचार झारखंड में मुद्दा नहीं बना, गोगो दीदी योजना को ठीक से समझा नहीं सकी। झारखंड ने जो मिल रहा है, उस पर भरोसा किया, जो मिलेगा, उस पर नहीं। इस चुनाव में आजसू साथ आयी थी, लेकिन उसका का बहुत लाभ भाजपा को नहीं मिल सका। इसका एक बड़ा कारण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जयराम महतो की पार्टी) रहा। झारखंड में कुड़मी-महतो की बड़ी आबादी है। इस समुदाय के युवा भाषा-संस्कृति व रोजगार के लिए आंदोलित रहे हैं। भाजपा से महतो मतदाताओं की दूरी बढ़ी है। आजसू की पकड़ महतो मतदाताओं पर रही है, लेकिन इस चुनाव में कुड़मी समुदाय के युवाओं की पहली पसंद जयराम महतो दिखे। भले ही एक सीट पर जेएलकेएम ने एक सीट जीती हो, पर उसने 14 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। जयराम महतो के दल के प्रत्याशियों ने 20 हजार से लेकर 70 हजार से ज्यादा वोट हासिल किये, जो उनकी ताकत बताता है। अब हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से सरकार बन रही है। मजबूत सरकार होगी, लेकिन चुनौतियां बहुत होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनाव में की गयी घोषणाओं को लागू करने की। राज्य की आय सीमित है। इसे बढ़ाना होगा। केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकार है। राज्य और केंद्र दोनों को चुनावी टकराहट को भूलना होगा। बेहतर तालमेल, आपसी सम्मान, राज्य-केंद्र के बीच संबंध से आगे की यात्रा सुखद होगी। राज्य को पैसा न मिले, खजाना खाली हो जाये तो विकास का काम ठप हो जायेगा।

संघ प्रमुख के अनुसार राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर तप आवश्यक

कृष्णमोहन झा

विज्ञान और अध्यात्म के बारे में यह एक आम धारणा है कि ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इस धारणा का खंडन करते हुए कहा है कि कि अध्यात्म और विज्ञान में परस्पर कोई विरोध नहीं हैं , अगर व्यक्ति के अंदर आस्था हो तो अध्यात्म और विज्ञान, दोनों ही उसके साथ न्याय करते हैं लेकिन अगर जिसको अपने साधन और ज्ञान का अहंकार है उसे अध्यात्म और विज्ञान में ज्ञान नहीं मिल सकता।? संघ प्रमुख ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि श्रद्धा में अंधत्व का कोई स्थान नहीं है। जानो और मानो यही श्रद्धा है। संघ प्रमुख ने कहा कि गत 2000 वर्षों में विश्व अहंकार के प्रभाव में चला है । यह अपनी ज्ञानेंद्रिय से मैं जो प्राप्त करता हूं वही सही है । इसी सोच के साथ मानव तब से चला है जब से विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है लेकिन यही सब कुछ नहीं है। विज्ञान का भी एक दायरा है , एक मर्यादा है ,इसलिए यह मानना ग़लत है कि विज्ञान के आगे कुछ नहीं है। संघ प्रमुख ने विगत दिनों नई दिल्ली में मुकुल कानिटकर द्वारा लिखित पुस्तक %बनाएं जीवन प्राणवान% के विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि की आसंदी से अपने विचारों को व्यापक संदर्भों में और स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि यही भारतीय सनातन संस्कृति की विशेषता है कि हमने बाहर देखने के साथ साथ अंदर देखना भी प्रारंभ किया और अंदर तह तक जाकर जीवन के सत्य को जान लिया। इसका और विज्ञान का विरोध होने का कोई कारण नहीं है। जानो तब मानो । अध्यात्म में भी यही पद्धति है। साधन अलग हैं । अध्यात्म में साधन मन है।मन की ऊर्जा प्राणों से आती है। प्रबल प्राण शक्ति व्यक्ति को आगे ले जाने की सामर्थ्य प्रदान करती है।

संघ प्रमुख ने जीवन में तप को महत्वपूर्ण बताते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर तप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ों में एक प्राण शक्ति है । भारत में भी एक प्राणशक्ति है जो हमारे सामने है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। वह प्राण हर व्यक्ति और हर चीज में है। वह प्राण 22 जनवरी को दिखाई दिया जिस दिन अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राममंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कार्यक्रम

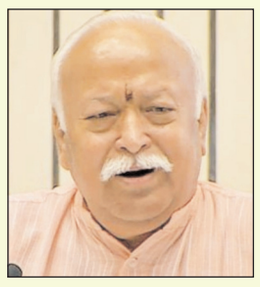

संपन्न हुआ । संघ प्रमुख ने कहा कि जब दुनिया में कहीं संकट आता है तो भारत तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आता है। भारत कभी यह नहीं देखता कि वह देश हमारा मित्र है अथवा शत्रु है। भारत की चेतना के पीछे यही प्राण दिखाई देता है। यही भारत की पहचान है।

वर्तमान समय में अपरिहार्य जीवन मूल्यों पर आधारित इस अनमोल पुस्तक के विमोचन समारोह में पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरि एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। अवधेशानंद गिरि ने अपने व्याख्यान में कहा कि प्राण का आधार परमात्मा है जो सर्वत्र है । प्राण की सत्ता परमात्मा से ही है। उसमें स्पंदन है । उसी से चेतना है। उसी से अभिव्यक्ति है, उसी से रस संचार है और वही जीवन है। पुस्तक लेखन के मुकुल कानिटकर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि परमात्मा की सहज अभिव्यक्ति प्राण है और उसकी व्याख्या इस पुस्तक में की गई है।

इस अवसर पर पुस्तक के लेखक मुकुट कानिटकर ने पुस्तक लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सब कुछ वैज्ञानिक है। आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, स्थापत्य के साथ ही दिन चर्या तथा ऋतुचर्या के सभी नियम भी बिना कारण के नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में प्राण आप्लावित है। लेखक ने आशा व्यक्त की कि नयी पीढ़ी के मन में उठने वाले सामान्य संदेहों के शास्त्रीय कारण स्पष्ट करने में उनकी पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश सिंह ने भी अपने व्याख्यान में कहा कि आज की पीढ़ी तर्क प्रधान पीढ़ी है लेकिन तर्क एक सीमा तक ही सही है। योगेश सिंह ने पुस्तक की विषयवस्तु की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक को पढ़कर जीवन से संबंधित लाइफ स्टाइल को समझने का मौका मिलेगा। इस पुस्तक में सभी को कुछ न कुछ नया मिलेगा।प्रो. योगेश सिंह ने कहा 100 वर्ष पुराने दिल्ली विश्वविद्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को अविस्मरणीय पल बताया।

ये काली काली आंखें में अपने किरदार के लिए गुरमीत चौधरी ने घटाया 10 किलो वजन

अभिनेता गुरमीत चौधरी को ये काली काली आंखें के नए सीजन में अपने दमदार किरदार में देखा जा सकता है। अपने इस खास किरदार के लिए अभिनेता ने अपने हेयर स्टाइल से लेकर अपने वजन घटाने पर भी काम किया। सीरीज में इस खास किरदार निभाने को लेकर गुरमीत ने काफी मेहनत की है। अपनी भूमिका में जान डालने के लिए अभिनेता ने सख्त डाइट और हैवी वर्कआउट से अपना लगभग 10 किलो तक वजन घटाया। ये काली काली आंखें में काम करने और अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेता गुरमीत ने कहा, सीरीज में गुरु का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। इसके साथ ही यह बेहद रोमांचक भी रहा। मेरे निर्देशक सिद्धार्थ सेनगुप्ता के पास मेरे किरदार के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, जिसके लिए मुझे बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ी। आगे कहा, मैंने इसके लिए कई एक्टिंग वर्कशॉप में भाग लिया, अपने लंबे बाल छोटे करवाए और वजन घटाने के लिए सख्त डाइट का पालन किया। मनचाहा लुक पाने के लिए मैं रोजाना बांद्रा में दौड़ने जाता था और आखिरकार मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। उन्होंने कहा कि इस सीरीज में काम करना मेरे लिए बेहद ही एक खास तरह का अनुभव था। मैं इसके लिए सिद्धार्थ सर का आभारी हूं, जिन्?होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझमें गुरु के किरदार को देखा। ये काली काली आंखें नेटफ्लिक्स पर एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसे सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने बनाया और निर्देशित किया है। इस सीरीज में श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही सौरभ शुक्ला, सूर्या शर्मा, अरुणोदय सिंह और बृजेंद्र काला भी सहायक भूमिकाओं में हैं। इस सीजन में गुरमीत चौधरी की भी एंट्री हुई है, जो पूर्वा का दोस्त है और उसे सुरक्षित घर वापस लाने की कसम खाता है। यह अस्तित्व का एक खतरनाक खेल है, और इस सीजन में गुरमीत चौधरी की दमदार एंट्री के साथ, दांव और भी बढ़ गए हैं। एजस्टॉर्म वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित, ये काली काली आँखें सीजन 2, 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। गुरमीत ने 2009 की टेलीविज़न सीरीज़ रामायण में देबिना बनर्जी के साथ राम की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई। इसमें देबिना ने सीता की भूमिका निभाई थी। अभिनेता ने गीत-हुई सबसे पराई, पुनर्विवाह, झलक दिखला जा, नच बलिए 6, फियर फैक्टर-खतरों के खिलाड़ी (सीजन 5) जैसे शो का हिस्सा ले चुके हैं। बॉलीवुड में गुरमीत की पहली फिल्म 2015 में आई थी।

सामंथा ने बताया कैसे तलाक के बाद ध्वस्त हो गईं जीवन से जुड़ी योजनाएं

सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्या ने साल 2021 में तलाक की घोषणा की थी। दोनों ने साल 2017 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद अभिनेत्री ने अनुपमा चोपड़ा के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि जीवन के लिए उनके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। अब उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेत्री तलाक को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने कहा, मेरा मतलब है, 2021 में मेरे निजी जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसे लेकर वास्तव में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी सभी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। भविष्य में मेरे लिए जो कुछ भी है, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। अभिनेत्री ने तलाक के बाद हुई आलोचनाओं को लेकर कहा, मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही गई जो बिल्कुल झूठ थीं। मुझे याद है कि जब चीजें वास्तव में बहुत खराब थीं। मेरे खिलाफ पूरी तरह से झूठ फैलाए जा रहे थे, तब मैंने खुद से यह बातचीत की थी। कई बार ऐसा हुआ जब मैं सामने आकर कहना चाहती थी कि यह सच नहीं है, मैं आपको सच बताती हूं।

श्वेता त्रिपाठी की दर्शकों से गुजारिश

महिला केंद्रित कहानियों को कीजिए सपोर्ट

श्वेता त्रिपाठी ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में उम्दा काम किया है। इस समय वह अपनी नई वेब सीरीज ये काली काली आंखें 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसमें उन्होंने काफी अलग रोल निभाया है। लेकिन इसके बावजूद वह मानती हैं कि अब भी महिला कलाकारों को उतने अच्छे रोल नहीं मिलते हैं, जितने की मिलने चाहिए। पुरुष कलाकारों को मिलती हैं अच्छी कहानियां हाल ही में एक इंटरव्यू में श्वेता त्रिपाठी कहती हैं कि पुरुष कलाकारों को बेहतर कहानियां मिलती हैं। इसलिए उनकी ख्वाहिश भी पुरुष किरदार निभाने की है। इसके अलावा वह दर्शकों से भी गुजारिश करती हैं कि महिला प्रधान फिल्मों और शो का समर्थन करें।

ये काली काली आंखें 2 के किरदार से खुश

श्वेता त्रिपाठी आगे कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरे किरदार एक-दूसरे से अलग हों। वेब सीरीज ये काली काली आंखें 2में शिखा का किरदार मुझसे बहुत अलग है और मैं उसकी दुनिया में कदम रखने की चुनौती का आनंद ले रही हूं। इस सीरीज की कहानी थ्रिलर वाली है, जिसमें श्वेता के साथ ताहिर राज नजर आ रहे हैं।

मिर्जापुर में किया था दमदार रोल

श्वेता त्रिपाठी ने वेब सीरीज मिर्जापुर में भी गोलू का किरदार निभाया था। इसमें वह काफी दमदार किस्म के किरदार को निभाती हुई दिखीं। दर्शकों ने उनको इस रोल में काफी सराहा। उनके साथ इस सीरीज में कई उम्दा कलाकार भी थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी और अली फजल जैसे नाम शामिल रहे।

आगे भी अच्छा काम करेंगी

आगे भी श्वेता का मन अच्छी और बेहतरीन फिल्में करने का है। इस समय तो वह वेब सीरीज ये काली काली आंखें 2 पर ही ध्यान दे रही हैं। वह जानना चाहती हैं कि दर्शक इस सीरीज को कितना पसंद करते हैं। इस वेब सीरीज की सफलता श्वेता के करियर में बहुत ज्यादा ही मायने रखती है।

तापसी ने शाहरुख के व्यक्तित्व पर की बात

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जितनी तारीफें उनकी शानदार अभिनय क्षमता के लिए मिलती हैं, उतनी ही तारीफें उन्हें उनके व्यवहार के लिए मिलती है। हाल में ही शाहरुख के साथ फिल्म डंकी में काम कर चुकीं अभिनेत्री तापसी पन्नू ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने किंग अभिनेता की बुद्धिमता, उनकी मौजूदगी आदि चीजों को लेकर बात की है। तापसी ने कहा कि शाहरुख में कुछ ऐसे गुण हैं, जो उनको दूसरों से अलग करते हैं। वो अपने आप में बेजोड़ हैं। तापसी ने डंकी के दौरान शाहरुख खान के साथ काम करने को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिनकी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति ही नहीं, बल्कि ऑफ-स्क्रीन उपस्थिति भी होती है। वे बहुत पढ़े-लिखे हैं और आपसे कोई भी गहन बातचीत कर सकते हैं। तापसी ने शाहरुख खान को एक संपूर्ण व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख के पास बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर है और उनका दिमाग बातचीत के दौरान काफी सक्रिय भी रहता है, जो उन्हें एक संपूर्ण व्यक्ति बनाती है, जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से काफी अलग करती है। तापसी पहले ऐसी फिल्मी हस्ती नहीं हैं, जिन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार के व्यक्तित्व की तारीफ की।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त होंगी जैकलीन

जैकलीन फर्नांडीज का नाम काफी समय से ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जोड़ा जाता रहा है। हाउसफुल 5 की अभिनेत्री ने हमेशा सुकेश के नाम से जुड़े सभी अवैध मामलों से अपने संबंधों से इनकार किया है। इस बीच, अभिनेत्री के वकील ने तर्क दिया है कि जैकलीन सुकेश के अवैध मामलों से अनजान थीं, और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने दलील दी है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी अपराध का हिस्सा नहीं थीं। फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र से संबंधित है। अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि फर्नांडीज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें चंद्रशेखर से जो गिफ्ट मिले थे, वे ठगी के पैसे से खरीदे गए थे। उन्होंने कहा, आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता दिखाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने विजय मदनलाल चौधरी के मामले में पिछले फैसले का भी हवाला दिया, जिसका अर्थ है कि जांच के दौरान जब्त की गई सभी संपत्ति आवश्यक रूप से अपराध की आय नहीं है। अग्रवाल ने यह भी तर्क दिया कि एक ही तथ्य पर दो मामले नहीं चलाए जा सकते। उन्होंने कहा कि अदिति सिंह से जबरन वसूली के एक मामले में मकोका के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और अभिनेत्री उस मामले में गवाह हैं। इसलिए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह किसी अपराध सिंडिकेट का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया है।

3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

एएनआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब फर्नांडीज द्वारा उस आरोप पत्र के खिलाफ दायर याचिका में अपनी दलीलें पेश करेगा, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है, जहां ईडी के विशेष वकील की दलीलें सुनी जाएंगी।

तेलुगु फिल्म बेबी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे बाबिल-कृति

कला और फ्राइडे नाइट प्लान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता बाबिल खान अब बॉलीवुड में बड़ा धमाल मचाने को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबिल जल्द ही हिट तेलुगु फिल्म बेबी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। वह इस फिल्म में आनंद देवरकोंडा वाले किरदार को निभाते दिखेंगे। सूत्रों के अनुसार फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री की तलाश अभी जारी है। तेलुगु संस्करण में वैष्णवी चैतन्य की अदाकारी को दर्शकों ने खूब सराहा था। वहीं, हिंदी संस्करण के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कृति शेट्टी के नाम की चर्चा जोरों पर है। बाबिल और कृति के फिल्म में नजर आने की फिलहाल कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, दोनों ही कलाकारों के एक साथ नजर आने की चर्चा से फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।

सुपर 30 में दिख चुकी हैं कृति

माना जा रहा है कि बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए यह फिल्म बाबिल खान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कृति शेट्टी के लिए भी यह फिल्म बॉलीवुड रास्ते खोलने में कारगर साबित हो सकती है। इससे पहले कृति को सुपर 30 में एक छात्रा की भूमिका में देखा गया था।

द रेलवे मेन से बाबिल ने बटोरी थी सुर्खियां

वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले साल बाबिल को वेब सीरीज द रेलवे मेन में देखा गया था। इस शो में दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी के बीच बाबिल ने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित इस शो में उन्होंने इमाद रियाज नाम के शख्स की भूमिका निभाई थी। वहीं, कृति को हाल ही में मलयालम फिल्म एआरएम में देखा गया था। यह इस इडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म थी।

इस वजह से मल्लिका शेरावत ने ठुकरा दी 'द रॉयल्स'

अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने राजकुमार राव की फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड के रूप में नजर आईं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें शुरू में नेटफ्लिक्स शो 'द रॉयल्स' का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। यह एक मॉडर्न इंडियन रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। इस शो में उन्हें ईशान खट्टर की ऑनस्क्रीन मां की भूमिका के लिए चुना गया था। आइए जानते हैं अभिनेत्री यह ऑफर क्यों ठुकरा दिया था। मल्लिका ने ईशान खट्टर की ऑनस्क्रीन मां की भूमिका को ठुकराने का कारण भी बताया। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मुझसे कुछ वादा किया गया था और जो अनुवाद किया गया वह मुझे पेपर पर बहुत ही बेकार लगा। मुझे धोखा और निराश महसूस हुआ, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले मल्लिका की टीम ने बताया, मल्लिका ने प्रोडक्शन टीम के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फरवरी में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। भूमिका शुरू में किए गए वादे के अनुरूप नहीं थी। कई चर्चाओं के बाद, उन्होंने आखिरकार इसे छोड़ने का फैसला किया। 'द रॉयल्स' में भूमि पेडनेकर, जीनत अमान, चंकी पांडे और नोरा फतेही, चंकी पांडे और डिनो मोरिया, विहान समत, काव्या त्रेहान, सुमुखी सुरेश, उदित अरोड़ा, लिसा मिश्रा और ल्यूक केनी अभिनेत्री की क्षमता का हुआ कम उपयोग मल्लिका ने यह भी साझा किया कि उन्हें लगता है कि कॉमेडी शैली में उनका कम उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा, लोगों ने अभी भी मेरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। मैं चाहती हूं कि इंडस्ट्री मेरी कॉमिक टाइमिंग और मेरी क्षमता का अधिक से अधिक कॉमेडी में उपयोग करें, क्योंकि मुझे कॉमेडी करना पसंद है। मुझे लगता है कि कॉमेडी में मेरा कम उपयोग किया गया है और मैं चाहती हूं कि इंडस्ट्री मुझे अधिक से अधिक कॉमिक भूमिकाएं दे। साथ ही, मैं अब ऐसी भूमिकाएं करना चाहती हूं, जिसमें दम हो।

फौजा के रीमेक पर राज शांडिल्य बोले

दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह पर आधारित फौजा के रीमेक को लेकर निर्माता राज शांडिल्य ने बात की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी कहानी है, जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करती है, उन्हें यह फिल्म हिंदी सिनेमा में लाने पर गर्व है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के निर्माता, राज शांडिल्य और विमल लाहोटी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'फौजा' का हिंदी में रीमेक के लिए टीम बनाई है। राज और विमल ने रीमेक के अधिकार हासिल कर लिए हैं। राज शांडिल्य के इस बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण उनके बैनर कथावाचक फिल्म्स के तहत किया जाएगा। फिल्म के बारे में बात करते हुए शांडिल्य ने कहा, फौजा एक ऐसी कहानी है, जो भाषा और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करती है। मुझे हिंदी सिनेमा में फौजा लाने पर गर्व है। 'फौजा' वास्तव में असाधारण साहस और भावना की कहानी है, जो देश भर के दर्शकों के द्वारा अनुभव की जाने योग्य है। मेरा लक्ष्य भी यही है कि एक ऐसी फिल्म तैयार हो जो हिंदी भाषी दर्शकों के साथ ही सभी को पसंद आए। निर्माता विमल लाहोटी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा, फौजा' उत्कृष्ट क्षेत्रीय सिनेमा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम प्रभावशाली कहानी कहने में विश्वास करते हैं और फौजा का हिंदी रीमेक असाधारण क्षेत्रीय सिनेमा को दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक कदम है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। 'फौजा' का हिंदी में निर्माण एक ऐसी कहानी को फिर से बताने का एक अविश्वसनीय अवसर है, जिसने पहले ही कई लोगों के जीवन पर शानदार असर डाला है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग ने किया आमंत्रित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर, 2024 को देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस को दिए गए अपने अंतरिम जवाब में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची में अपडेट प्रक्रिया को दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। साथ ही मतदान डाटा के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने मतदान डाटा में कोई विसंगति नहीं होने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि यह सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र के अनुसार उपलब्ध है और सत्यापित है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस हार से उबर नहीं पा रही : ललन सिंह

पटना। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता के चुनाव आयोग को अपशब्द कहने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस हार से उबर नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है। अब वह हार को कवर-अप करने के लिए सदन नहीं चलने देना तथा अन्य अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने अपना फैसला दे दिया। वे बहुत उछल रहे थे। अब बाहर में ऐसे ही उछलने का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरीके से उछलते रहते हैं। वहीं, स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के बिहार विधानसभा में हंगामा से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम है? बिजली जला रहे हैं तो बिल का भुगतान होना चाहिए। स्मार्ट मीटर वही है। आप जितना चार्ज करिए, उतना बिजली जलाइए, उतना भुगतान कीजिए। इसमें समस्या कहां है।

प्रचंड जीत के बाद पहली बार वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार शनिवार को केरल पहुंची है, जहां वो अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगी। सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी की ये पहली वायनाड यात्रा है जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पहली यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी है। इससे पहले दिन में गांधी परिवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने आवास से बाहर निकलते हुए फोटो सामने आए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सत्यन मोकेरी को 4,10,931 मतों के अंतर से हराकर वायनाड लोकसभा सीट हासिल की है। कांग्रेस के गढ़ वायनाड में प्रियंका गांधी, भाजपा की नव्या हरिदास और सीपीआई के सत्यन मोकेरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। वायनाड सीट उनके भाई राहुल गांधी द्वारा खाली की गई थी, जो पहले वायनाड का प्रतिनिधित्व करते थे।

महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिले: शिरसाट

मुंबई। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने शनिवार को कहा कि पार्टी को महाराष्ट्र की नयी सरकार में गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। शिरसाट ने कहा कि शिंदे की सकारात्मक छवि और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल और मिले होते तो वह और ज्यादा योगदान देते। औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक ने कहा, ''गृह विभाग पार्टी (शिवसेना) को मिलना चाहिए। यह विभाग (आमतौर पर) उपमुख्यमंत्री के पास होता है। अगर मुख्यमंत्री गृह विभाग को संभालते हैं तो यह सही नहीं है।'' निवर्तमान सरकार में गृह विभाग देवेंद्र फड़नवीस के पास है। शिरसाट ने कहा, ''शिंदे को महायुति सरकार का चेहरा बनाकर भाजपा को निश्चित रूप से फायदा हुआ।

पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी

पूर्णिया। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। इसमें कहा कि 24 घंटे में तुम्हारी हत्या कर देंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। तुम्हारे गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुझे हैप्पी बर्थडे लॉरेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपना आखिरी दिन के मजे कर लो। इस नंबर से धमकी आई है, वो पाकिस्तान का है। +92 336 0968377 नंबर से धमकी वाला मैसेज भेजा गया है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए सात सेकेंड का धमाके से जुड़ा एक वीडियो भी सांसद के मोबाइल नंबर पर भेजा है। इस मैसेज के बाद से पूर्णिया में सांसद के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में ही हैं।

अडानी अमेरिका में अपराधी, लेकिन पीएम मोदी उन्हें दोषी नहीं ठहराएंगे: राहुल

वायनाड। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी रिश्वत मामले में अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी को बचाने का आरोप लगाया। वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं। हम भावनाओं, प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वे नफरत, विभाजन, हिंसा के बारे में बात करते हैं। संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

राहुल ने दावा किया कि प्रधान मंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। पीएम मोदी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी को संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधी कहा गया है। भारत में, हम उसे दोषी नहीं ठहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास पूरी सरकार है। उनके पास मीडिया है। पैसा, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें तो बस जनता की भावना है। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि हर बार लोगों की भावना ही जीतती है। मुझे विश्वास है कि हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे।

यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी की आलोचना की है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी के साथ-साथ दो अधिकारियों, अडानी ग्रीन एनर्जी के सागर अडानी और विनीत जैन को दोषी ठहराए जाने के बाद आई। अभियोग में उन पर 2 बिलियन डॉलर के सौर ऊर्जा अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए 2020 और 2024 के बीच 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।

मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम अडानी को जांच से बचा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधबी पुरी बुच को उनके घोटालों में अडानी का कथित रूप से समर्थन करने के लिए हटाने की भी मांग की। राहुल गांधी ने बीजेपी के नारे एक है तो सुरक्षित है पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अडानी साथ हैं तो सुरक्षित हैं। भारत में अडानी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। यहां मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है और अडानी 2,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने के बाद आजाद घूम रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं।

वायनाड के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करूंगी : प्रियंका

वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद दो दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि वह वायनाड वापस आकर बहुत खुश हैं और यहां के लोगों की मदद के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने यहां करीपुर हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से कहा, %मैं यहां वापस आकर बहुत खुश हूं और काम शुरू करने के लिए तैयार हूं। मैं वायनाड के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए जो कुछ भी कर सकती हूं, वह करने को तैयार हूं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र की सांसद के रूप में यह उनका पहला दौरा है।

ईवीएम मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- राहुल गांधी इस्तीफा दें

नई दिल्ली। चुनावी नतीजों के बाद लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी, उनके सीएम और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और यह घोषणा करें कि मतपत्रों की वापसी पर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो शायद उनका भरोसा भी बढ़ेगा। नहीं तो यह आरोप केवल खोखले शब्द ही बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी ध्यान रखें वे भी ईवीएम आधारित चुनाव प्रक्रिया से ही चुनकर सांसद बने हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अदालत का रुख करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पद इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं जिस पर उनकी पार्टी सवाल उठा रही है।

उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ईवीएम पर उस दिन सवाल उठाया जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। कांग्रेस जल्द इतिहास के पन्नों तक सीमित हो जाएगी।

भारत सरकार कर रहा हिंदू अल्पसंख्यकों की मदद

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही घटनाओं को लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत की मजबूत आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत का यह कर्तव्य है कि जब अल्पसंख्यकों को कहीं भी उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वह अपनी आवाज उठाए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सरकार ने अपना रुख बता दिया है। उच्चायोग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

अखिलेश यादव बन रहे दंगाइयों की ढाल

संभल हिंसा को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दंगाइयों की ढाल बन रहे हैं। उनकी पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य शांति बहाली के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के बजाय हिंसा भड़काने में शामिल हैं। जब राज्य में उसकी सरकार थी तो अक्सर दंगे भड़कते थे। विपक्षी पार्टी को पुलिस पर भरोसा नहीं है।

शरद पवार का ईवीएम में हेरफेर का आरोप

चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता-धन का दुरुपयोग हुआ

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को महायुति के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अब इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। इस पर राकांपा-एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पूरे चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया। राकांपा-एसपी नेता ने बताया कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। शरद पवार ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉ. बाबा अधव से मुलाकात की। बता दें कि बाबा अधव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

90 वर्षीय बाबा अधव ने गुरुवार को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के निवास फुले वाडा में तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस, शिवसेना(यूबीटी) और राकांपा-एसपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी।

पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने बताया कि ईवीएम में वोट जोड़े जाने के कुछ नेताओं के दावों में सच्चाई है। हालांकि, फिलहाल उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हुए चुनावों ने कई लोगों को बेचैन कर दिया। हर दिन सुबह 11 बजे संसद में विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। वे अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसदीय लोकतंत्र का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह ठीक नहीं है और इसके लिए हमें लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा।

राकांपा-एसपी नेता ने आगे कहा, ईवीएम में वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों ने दोबारा गिनती की मांग की है। इस मामले में जो भी संभव होगा किया जाएगा। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया है। देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है।

बालासाहेब थोराट के आरोपों को बताया चौंकाने वाला

शरद पवार ने बताया कि उन्होंने सुना कि बाबा अधव ने इस मुद्दे को उठाया और फुले वाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका विरोध लोगों में उम्मीद जताता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। उन्होंने बालासाहेब थोराट जैसे नेता के इन आरोपों को चौंकाने वाला बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, यह केवल थोराट नहीं, बल्कि कई लोगों ने ऐसी जानकारी दी है। कांग्रेस ने इस मामले में बैठक की। चर्चा हुई कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को साथ में मिलकर उठाएगा। मुझे यकीन है कि सोमवार तक कुछ निर्णय लिया जाएगा।

बता दें कि इस महीने महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति (भाजपा, शिवसेना, राकांपा) ने 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महाविकास अघाड़ी 46 सीटों को जीतने में कामयाब रही।

खेल
प्रमुख समाचार

एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, हेजलवुड बाहर

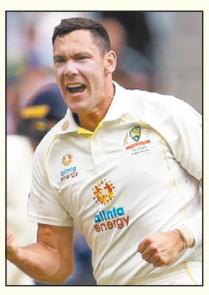

एडिलेड। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जिसका पहला टेस्ट भारत ने जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वहीं दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में 6 दिसंबर से खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले मेजबान टीम को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। दरअसल, मिचेल मारश की फिटनेस को लेकर चिंताओं के बीच दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पिंक बॉल टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड ने पर्थ टेस्ट में 5 विकेट झटके थे।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड की जगह पर खेलने वाले खिलाड़ी के नाम की घोषणा कर दी है। सीए ने कहा कि सीन एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट को 6 दिसंबर एडिलेड ओवल में होने वाले डे-नाइट टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, स्कॉट बोलैंड को हेजलवुड के स्थान पर प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की ज्यादा संभावना है। बोलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। वह जुलाई 2023 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं।

हेजलवुड का न होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है। दाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज पर्थ टेस्ट में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे। उन्होंने पारी कमें 29 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। भारत 150 रन पर आउट हो गया था। दूसरी पारी में 21 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिए। पिछली बार जब भारत एडिलेड में खेला था, तब भी ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हेजलवुड थे। उन्होंने पांच ओवर में 8 रन देकर 5 विकेट झटके थे। भारत 36 पर पर आउट हो गया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

विश्व बैंक हरियाणा को अगले 5 वर्षों में वित्तीय सहायता देगा

चंडीगढ़ । विश्व बैंक अगले पांच वर्षों में हरियाणा को पिछले 50 वर्षों के बराबर वित्तीय सहायता देगा। विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने यह जानकारी दी। उन्होंने यहां राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान शिक्षा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। आगामी वित्तपोषण के बारे में कौमे ने कहा, हमने पिछले 50 वर्षों में जितना वित्तपोषण दिया है, अगले पांच वर्षों में उतना ही देंगे.... मैं इस बात को लेकर काफी उत्साहित हूं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में हरियाणा की बड़ी भूमिका के लिए हम मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को ऋण के रूप में सीधे दिए गए एक अरब डॉलर के अलावा राज्य को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित अखिल भारतीय परियोजनाओं से भी लाभ हुआ है।

दिसंबर तक ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से ग्रामीण ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की अपील की है। मंत्री ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आठ आरआरबी के साथ शुक्रवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डिजिटल समावेशन के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सीतारमण ने आरआरबी को डिजिटल सेवाओं के लिए ग्राहकों को शामिल करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए दिसंबर 2024 तक इस कार्य को पूरा करने की समय सीमा तय की। उन्होंने आरआरबी को अपने प्रायोजक बैंकों के समर्थन से अपने ग्राहकों के बीच डिजिटल सेवाएं अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

ओटीपी के जरिए जालसाजी करने वालों पर लगाम

नई दिल्ली। 1 दिसंबर, 2024 से भारत में कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले बदलाव होने वाले हैं। इनमें फर्जी ओटीपी को रोकने के लिए संशोधन भी शामिल है। संदिग्ध ओटीपी पर अंकुश लगाने और स्कैमर्स से लोगों को होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों से संदेश ट्रेसबिलिटी प्रदान करने के लिए कहा है। निर्देश का पालन करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2024 था। इस विनियमन के तहत दूरसंचार कंपनियों को सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआती समय सीमा 31 अक्तूबर थी, लेकिन सेवा ऑपरेटरों की मांग के बाद, ट्राई ने इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। कुछ रिपोर्टों ने दावा किया कि इससे ग्राहकों को ओटीपी प्राप्त करने में देरी हो सकती है, लेकिन ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में ऐसे अफवाहों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।

नहाने वाले साबुन की कीमतों में 7-8 प्रतिशत का उछाल

नईदिल्ली। घरेलू सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियां एचयूएल और विप्रो ने पाम ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते साबुन के दामों में 7-8 प्रतिशत का इजाफा किया है। पाम ऑयल, साबुन बनाने का एक अहम कच्चा माल है, और इसकी कीमतों में उछाल का असर अब सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। सिर्फ साबुन ही नहीं, एचयूएल और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियों ने हाल ही में चाय की कीमतों में भी इजाफा किया है। इसकी वजह है अनियमित मौसम, जिसने चाय उत्पादन पर बुरा असर डाला है। पाम ऑयल और चाय दोनों ही रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों का बजट गड़बड़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे माल की लागत में इजाफे के कारण कंपनियां कीमतें बढ़ाने को मजबूर हुई हैं।

वित्तीय दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का नतीजा

अजीत रानाडे

देश के आर्थिक उत्पादन में 14 प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसकी राजधानी मुंबई देश की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी भी है। इस शहर से देश कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय सहित प्रत्यक्ष करों का एक बड़ा हिस्सा एकत्र करता है। मुंबई का रियल एस्टेट सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। राज्य का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह है, जो सभी कंटेनरीकृत कार्गो का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा संभालता है, और देश में कुल टन भार के मामले में शीर्ष पांच बंदरगाहों में से एक है। यह समर्पित माल गलियारों से निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह भारत के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। यहां कई सड़क मार्ग, मेट्रो और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं, जो महाराष्ट्र की आर्थिक शक्ति बढ़ायेंगी। वास्तव में, इसकी मंशा अगले कुछ वर्षों में भारत की पहली एक ट्रिलियन डॉलर की अर्ध-संप्रभु अर्थव्यवस्था बनने की है। इसलिए स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में सरकार बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा पुरस्कार है।

माझी लड़की बहिन (मेरी प्यारी बहन) योजना का मतदाताओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, अब दो करोड़, पचास लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद लाभ के रूप में 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। महायुति के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार, चुनाव के बाद यह राशि 2,100 रुपये हो जायेगी। इससे सरकारी खजाने पर कुल अतिरिक्त बोझ लगभग 63,000 करोड़ प्रतिवर्ष का होगा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या राज्य में लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना पर खर्च की गयी राशि

से अधिक बैठेगा। पहले से ही महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि यहां 67 प्रतिशत व्यय 'राजस्व मदों' पर होता है जिसमें वेतन, पेंशन और पिछले ऋण पर ब्याज भुगतान शामिल हैं। अगले वर्ष तक यह ऋण बढ़कर 7.8 लाख करोड़ हो जायेगा, जिससे अकेले वार्षिक ब्याज भुगतान का बोझ लगभग 50,000 करोड़ हो जायेगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने विगत मई में सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर आगाह भी किया था। लड़की बहिन योजना के बिना भी राज्य को पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान की योजना बनानी होगी जो अगले सात वर्षों में देय होगी। यह राशि 2.75 लाख करोड़ है, जिसके लिए अब से हर वर्ष लगभग 40,000 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। यदि राज्य की विकास दर (और इस कारण कर राजस्व) बढ़ती है, तो इस सभी अतिरिक्त ऋण के बोझ का प्रबंधन संभव है। परंतु, कम से कम इस वर्ष विकास दर 5.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर से कम है। यह एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए आवश्यक 12 प्रतिशत से भी काफी कम है।

जिस राज्य में 2019 में राजस्व अधिशेष था, वहां अब राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल ऋण राज्य की जीडीपी के 20 प्रतिशत के आसपास पहुंच रहा है, जिसे राज्यों और केंद्र सरकार के संयुक्त वित्तीय जिम्मेदारी ढांचे के तहत अधिकतम सीमा माना जाता है। राजकोषीय दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के अल्पकालिक लाभों के कारण करदाता पर भविष्य में बोझ बढ़ेगा। लड़की बहिन (एलबी) योजना ने दूसरी योजनाओं को समाप्त नहीं किया है।

शून्य बिजली बिल और किसानों के लिए 15,000 रुपये, छात्रों के लिए 10,000 रुपये जैसी कई और रियायतें यहां दी जा रही हैं। एलबी योजना एक सफल फॉर्मूला रहा है जिसका इस्तेमाल झारखंड में भी किया गया और यह कम से कम एक दर्जन अन्य राज्यों में चल रहा है। परंतु इसका राजकोषीय स्थिति और इसके नतीजतन विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के साथ-साथ भविष्य के कर बोझ पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बारीक पड़ताल नहीं की जाती है।

वित्तमंत्री ने किया महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का अपने निवास कार्यालय से लांचिंग की। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन अरोरा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत, जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है और जिनमें महतारी वंदन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय मदद प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में भी सहायक होगी।

एक साथ होगा नगरीय निकाय-त्रिस्तरीय चुनाव, भाजपा की बैठक में बनी सहमति, सरकार जल्द करेगी घोषणा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में एक साथ नगरीय निकाय के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सहमति बनी. लेकिन महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष इस पर अभी सस्पेंस बरक़रार है. उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लेगी

बीजेपी के बस्तर सरगुजा बिलासपुर संभाग के भाजपा सांसद, विधायक और संभाग पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि नहीं, इस फैसले के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा. बहुत जल्द सरकार इस पर फ़ैसला लेगी.

अरुण साव ने कहा कि गांव व शहरों की विकास अवरूद्ध हो गई थी. राज्य में विष्णु देव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है. हमने 11 महीने में जो काम किया है, उसको लेकर जनता तक जाएंगे.

गांवों और शहरों में हुए विकास के काम को जनता तक लेकर जाएंगे. नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय चुनाव में बीजेपी की परचम लहराएगी.

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बैठक हुई है. महापौर, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष एवं त्रि स्तरीय चुनाव एक साथ होगा की नहीं इस पर चर्चा हुई है.

कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सभी इस बात पर सहमति हैं कि चुनाव एक साथ हो. बहुत ही जल्द सरकार इसको लेकर घोषणा करेगी.

सरकार की उपलब्धियों के आधार पर विजय पर्व मनाने और जनता का समर्थन जुटाने बनी रणनीति

राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ भाजपा कोर ग्रुप और सांसद-विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने किया। इसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य, विधायक और सांसद शामिल हुए। बैठक में संगठन चुनाव और आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि बीजेपी ने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान जनता को राहत देने वाले कई कार्य किए हैं, जिनके दम पर आगामी चुनावों में जनता का विश्वास जीतने का प्रयास होगा। बैठक में शामिल सभी सांसदों और विधायकों ने अपने सुझाव भी दिए है। आने वाले 13 से 25 दिसंबर तक सरकार के सालभर के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इन उपलब्धियों के आधार पर विजय पर्व मनाने और जनता का समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई गई है।

सरकार 21 क्विंटल के आधार पर खरीदी नहीं कर रही - दीपक

रायपुर। सरकार किसानों का 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं करना चाह रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में सोसायटी वार जो अनावरी रिपोर्ट बनाया गया उसमें 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में अनावरी रिपोर्ट षड़यंत्रपूर्वक 21 क्विंटल से कम 9, 10, 14, 16 क्विंटल बनवाया गया है। खरीदी अनावरी रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। कम खरीदी करने के बाद झूठा दावा किया जा रहा कि पूरा 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी हो रही है। सरकार प्रदेश के सभी जिलों की अनावरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे सच्चाई सामने आ जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि टोकन काटने के बाद भी किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे है, क्योंकि टोकन कटने की तारीख से 3 से 7 दिन बाद धान बेचने के लिये किसानों को बुलाया जा रहा है। ऑनलाइन 15 दिसंबर तक टोकन नहीं मिल रहा।

सोसाइटियों को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिये उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार भले ही घोषणा कर रही है पूरा धान खरीदेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से खरीदी हो रही उससे किसान चिंतित है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था, बारदानों की कमी तथा टोकन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों तथा मीलरों द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण किसान परेशान है। समितियों में बारदाने की कमी है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने का झूठा दावा कर रही है। सरकार किसानों को तथा समस्या उठाने वालों को धमकाने के बजाय कमियां दुरूस्त करें। धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था और सरकार द्वारा जारी फरमान के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही।

सरकार के द्वारा 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, इसमें से 30 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात लगभग 45 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 45 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नही। प्रतिदिन 3.5 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जायेगी तभी निर्धारित लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो पायेगी।

अच्छा नेता वही है जो नए नेता, नई टीम बनाकर संगठन को दें - नितिन नबीन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज संगठन पर्व प्राथमिक सदस्यता अभियान एवं सक्रिय सदस्यता अभियान, व संगठनों चुनावों की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा है कि सदस्यता अभियान की सफलता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का परचम किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य तय किया और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपेक्षा की थी छत्तीसगढ़ भाजपा से उसे लक्ष्य को हमने पूरा किया है और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का कार्य किया है। संगठन चुनावों के विषय कर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

कि अच्छा लीडर वही है जो नए नेता, नई टीम बनाकर संगठन को दें। नई टीम की कल्पना को बनाना है और सरकार को ताकत देना है। संगठन को ऊर्जा देना है। आप सबकी मेहनत और संगठन की ताकत से बनी सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए मोदी की गारंटी में किए बड़े वादों को पूरा कर दिया है और अन्य वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा इस पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरेगी। हमें चुनाव में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता तक जाना है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जनता से आशीर्वाद मांगना है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सदस्यता अभियान की सफलता के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसढ़ प्रदेश ने केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया सदस्यता लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारियों ने 86 दिनों में 60 लाख के सदस्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान की सफलता बताती है कि जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन भाजपा के ऊपर बढ़ता जा रहा है और सभी भाजपा के साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी देना सुनिश्चित करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा, महाराष्ट्र की जीत बधाई देते हुए कहा कि एंटी इनकंबेंसी अतीत की बात हो गई है जनता जानती है कि उनका विकास भाजपा के साथ ही संभव है अब देश प्रोइनकमबेंसी देख रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

कुलपति डा. चंदेल राष्ट्रीय रिसर्च फेलो चयन समिति के सदस्य बने

रायपुर। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को भारत सरकार के '' जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय'' के रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गठित इस चयन समिति में डॉ. चंदेल सहित देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के कुल 22 सदस्य रखे गये हैं। इस समिति के अध्यक्ष बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राकेश भटनागर हैं एवं उपाध्यक्ष जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति डॉ. मोहन सिंह चौहान को बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित इस प्रतिष्ठित चयन समिति का मुख्य कार्य देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को अनुसंधान हेतु फेलोशिप उपलब्ध कराना तथा उनका मार्गदर्शन करना है। डॉ. चंदेल का रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप चयन समिति में मनोनयन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है।

सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली

रायपुर। सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का भाजपा सरकार 1500 करोड़ से अधिक का भुगतान रोक कर रखी है जिसके कारण निजी अस्पताल वाले आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का ईलाज बंद करने की चेतावनी अनेकों बार दे चुके है। बकाया भुगतान करने की अस्पतालों ने अंतिम चेतवानी भी सरकार को दिया है। उसके बाद भी सरकार अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही है। यदि निजी अस्पतालों ने गरीबों का ईलाज बंद कर दिया तो गरीब वर्ग के लोग मुश्किल में पड़ जायेंगे। अनेक ऐसी बीमारियां है जिनका ईलाज निजी अस्पतालों में ही होता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों का ईलाज हो भी नहीं सकता। अत: सरकार इस मामले में त्वरित निर्णय ले। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 2018 की तुलना में ढाई गुना बेहतर विकसित किया था। सभी जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल के तौर पर विकसित किया था। ब्लॉक के अस्पतालों में भर्ती की सुविधाएं विकसित की थी।

रेहड़ी वालों को हटाना सरकार का अमानवीय कदम - कांग्रेस

रायपुर। सरकार द्वारा सड़कों के किनारे ठेले, खोमचे, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाये जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में भाजपा ने यह कार्यवाही किया है। ईमानदारी से मेहनत, मजदूरी करके सड़कों के किनारे ठेले आदि लगा कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वालो को हटाया जाना सरकार का तानाशाही पूर्ण कदम है। ठेले वालों को हटाने से पूर्व उन्हें समान हटाने का भी समय नहीं दिया गया उनके तैयार किये गये समानों को नष्ट कर दिया गया। हजार-दो हजार रू. की लागत लगाकर छोटे-छोटे होटल वालों ने जो खाद्य सामाग्री तैयार किया था उसे फेक दिया गया, उनके ठेलो को जेसीबी से तोड़ डाला गया। जसी बनाया गया, विरोध करने वालो को पुलिस से पिटवाया गया। अपने आपको हिन्दुओं की पार्टी होने का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार ने जो ठेले हटाया है उसमें 99 प्रतिशत से अधिक हिन्दू ठेले वाले थे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की कार्यवाही अनुचित और अमानवीय है। यदि कोई सड़क या यातायात में बाधक था उसे सूचना देकर कुछ दिन की मोहलत देकर हटाना था। अचानक आतातायी तरीके से हटाना भाजपा सरकार का गरीब विरोधी कदम है।

रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन की रुपरेखा बनाई

रायपुर। जिला कांग्रेस रायपुर किसानों के मुद्दे पर आंदोलित जिला कांग्रेस रायपुर द्वारा कांग्रेस भवन में आंदोलन की रूपरेखा बनाकर उधो राम वर्मा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने समस्या को विस्तार से जानकारी में ये बात कही किसानों की बारदाना, टोकन के एवं एक बार में में 3100+117 रु देने की मांग को लेकर जिला स्तरीय कमेटी, ब्लॉक स्तर में खरीदी केंद्र स्तरीय समिति बना है जो किसानों के हित में हर समस्या के लिए किसानों के साथ संघर्ष करने की बात, इसके लिए व्यवस्था में सुधार, किसानों को राहत हेतु जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर द्वारा जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की बात कही, बैठक में संविधान रक्षक दिवस कार्यक्रम के तहत बूथ, जोन एवं ब्लॉक स्तर में कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें जिले के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में शिव डहरिया पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती इसलिए टोकन, वारदाना एवं धान उठाव में लगातार अड़चन डाल रहे है, ताकि किसानों का धान खरीदना ही नहीं पड़े, हम सभी कांग्रेसजनों को मिलकर किसानों की समस्या के समाधान के लिए काम करना है। बैठक में छाया वर्मा पूर्व सांसद, डोमेश्वरी वर्मा, पंकज शर्मा, नंदलाल देवागन, प्रवीण साहू, पप्पू राजेंद्र बंजारे ने अपनी बात रखी।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमला रोकने केंद्र सरकार कठोर कदम उठाये

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताने वाली भाजपा की सरकार मौन क्यों हैं। नरेंद्र मोदी जो खुद को 56 इंच का सीना वाले बताते थे जो दावा करते थे की एक सिर के बदले दुश्मन देश के 10 सैनिकों के सिर को काट कर लेंगे। भाजपा जो दावा करती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का विश्व में डंका बज रहे। वह बांग्लादेश को लाल आज दिखाने में भयभीत क्यों है। भाजपा सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि वह इस मसले पर मौन है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमला रोकने केंद्र सरकार कठोर कदम उठाये। कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी जोर-जोर से बांग्लादेश के मुद्दा को लेकर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। भाजपा को बताना चाहिए मोदी सरकार ने बांग्लादेश के मसले पर अब तक क्या कार्यवाही की है हिंदुओ को सुरक्षा देने क्या प्रयास किये हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को वह दिन याद करना चाहिए जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला हुआ तब इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान में हमला करके वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और अलग बांग्लादेश का निर्माण किये है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लिनन प्रबंधन: यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त सेवाएँ प्रदान करने की पहल

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वातानुकूलित (एसी) श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छ, हाइजीनिक, अच्छी तरह से प्रेस (इस्त्री) किया हुआ और उच्च गुणवत्ता वाला लिनन प्रदान करने के लिए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, ताकि यात्री सुविधा एवं संतुष्टि में वृद्धि हो सके । यात्रियों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला लिनन प्रदान करने के प्रयास को सुनिश्चित करने हेतु - उच्च गुणवत्ता वाले लिनन की खरीद, आधुनिक और यंत्रीकृत वाशिंग सुविधाएं, यात्रियों के लिए बेड रोल्स के सेट को इको-फ्रेंडली पैकेजिंग में प्रस्तुत करना एवं मजबूत और प्रभावी परिवहन के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है । इसके साथ ही सभी लिनन सेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं । ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों में हैंडलूम के उच्च गुणवत्ता वाले बेडशीट्स प्रदान की जाती हैं । लिनन के भंडारण के लिए डिपो और ट्रेनों में उपयुक्त स्थान निर्धारित किए गए हैं ।

सभी लिनन प्रत्येक उपयोग के बाद धोए जाते हैं और उनकी स्थिति या आयु के अनुसार हटाए जाते हैं । कंबल कम से कम महीने में एक बार ड्राई-क्लीन किए जाते हैं । यात्रियों को बिना धोया या उपयोग किया हुआ कोई भी लिनन नहीं दिया जाता । प्रत्येक किट को इको-फ्रेंडली बैग (आकार: 30×42 सेमी) में पैक किया जाता है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और दुर्ग कोचिंग डिपो में क्रमश: 3 टन और 4 टन क्षमता वाली लॉन्ड्री यूनिट स्थापित किया गया हैं, जहां पर न्यूनतम दो शिफ्ट में काम किया जाता हैं । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग 16,000 लिनन सेट लोड किए जाते हैं । भारतीय रेल के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है ।

9 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 10 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 09 विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के साथ बस्तर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 10 चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों और संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. रमन जोगी को जिला अस्पताल बिलासपुर, डॉ. योगेश कुमार शर्मा जिला अस्पताल दुर्ग, डॉ आकांक्षा गुप्ता जिला अस्पताल जांजगीर चांपा, डॉ नवनीत सिंह ठाकुर जिला अस्पताल (एसएनसीयू) कबीरधाम, डॉ. भावना चौरे जिला अस्पताल खैरागढ़-गंडई-छुईखदान, डॉ नीरज कुमार जिला अस्पताल मुंगेली, डॉ अनिल खापर्डे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, डॉ उमा खापर्डे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, डॉ राजभान प्रजापति जिला अस्पताल सूरजपुर में पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी (संविदा) के जारी आदेश में डॉ आरूषि शर्मा, डॉ. अंकित सिंह राजपूत, डॉ, भुनेश्वर नेताम, डॉ शिवानी कोर्राम, डॉ, सुब्रत मल्लिक, डॉ. आकांक्षा दारियो, डॉ. रोहिणी राणा, डॉ. यामिनी कांगे, डॉ. अनिल कुमार पटेल व डॉ कुनाल सिंह साहू को बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.